2 साल बेमिसाल

2 Years of People's Governance

दिल्ली सरकार

आप की सरकार

ARVIND KEJRIWAL
Chief Minister, Delhi

www.delhi.gov.in

MANISH SISODIA
Dy. Chief Minister, Delhi

विषय सूची

विषय	पेज संख्या
मुख्यमंत्री का जनता के नाम संदेश	02
शिक्षा	03
स्वास्थ्य	12
जल	21
बिजली	25
दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड	27
पर्यावरण	30
परिवहन	37
लोक निर्माण	43
प्रशासनिक सुधार	48
कर सुधार	50
शहरी विकास	52
श्रम	53
ग्रामीण विकास	58
खाद्य आपूर्ति	60
महिला एवं बाल विकास	62
समाज कल्याण	63
पर्यटन	64
कला, संस्कृति एवं भाषा	68
Archaeology	70

दिल्ली सरकार के दो साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जनता के नाम संदेश

प्रिय दिल्लीवासियों,

आप की सरकार के दो साल पूरे होने पर अब तक के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने में मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। दिल्ली वालों ने देश के और दिल्ली के चुनावी इतिहास में अभूतपूर्व बहुमत देकर हमें चुना और काम करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

हमने 14 फरवरी, 2015 को दिल्ली की जनता की सेवा करने की शपथ ली थी। उस ऐतिहासिक मौके पर ही हमने स्पष्ट कर दिया था कि हमारा एकमात्र लक्ष्य ईमानदारी के साथ जन कल्याण के कामों को तय समय सीमा के भीतर और पारदर्शिता के साथ पूरा कराना है।

हम नियमित रूप से खुद को इस बात की याद दिलाते रहे कि हमारे घोषणा पत्र में शामिल 70 वादों को पूरा करने के लिए दिल्ली की जनता ने हमें प्रचंड बहुमत दिया है और इन वादों को हमें हर हाल में पूरा करना है।

सरकार के दो साल पूरा होने के मौके पर मैं अब तक हुए सभी विकास कार्यों का लेखा–जोखा आपके सामने रख रहा हूं। साथ ही ये भी भरोसा देना चाहता हूं कि आने वाले वर्षों में अन्य विकास कार्य भी पूरे हो जाएंगे और दिल्ली की प्रगति और तेजी से होगी।

दिल्ली में मौजूदा कानूनी जटिलताओं और संवैधानिक स्थितियों के कारण विकास कार्यों को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है लेकिन इस मौके पर मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि दिल्ली में सुचारु प्रशासन रास्ते में खड़ी की जाने वाली हर तरह की बाधाओं का मैं विरोध करूंगा।

मैं आशा करता हूं कि जनता के हित में और राजधानी के विकास के लिए हमारे प्रगतिशील एजेंडे पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार को अच्छे से काम करने दिया जाएगा।

मुझे आपसे ऐसी रचनात्मक आलोचनाओं और सुझावों की अपेक्षा है जिससे हम दिल्ली के लोगों की और बेहतर ढंग से सेवा कर सकें।

मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि दिल्ली सरकार के अब तक के विकास कार्यों पर बारीकी से नजर डालें।

शुभकामनाओं सहित

आपका,

अरविंद केजरीवाल

शैक्षिक आधारभूत संरचना का निर्माण

- 8000 नई कक्षाएं (तकरीबन 200 स्कूलों के बराबर ढांचागत निर्माण)
- 21 नए स्कूल भवन
- 54 स्कूलों में अत्याधुनिक सुविधाएं
- सभी कक्षाओं में ग्रीन बोर्ड
- स्वच्छता के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल
- लड़कों और लड़कियों के लिए अलग–अलग उपयोगी शौचालय
- आरओ वाले पेयजल की सुविधाएं
- सभी स्कूलों में सीसीटीवी सुरक्षा कैमरे लगाए गए
- शिक्षकों के निर्माणाधीन स्टाफ रूम को बढ़िया रूप देना
- नए स्कूल भवनों के निर्माण की योजना है
- नए स्कूलों के लिए भूखंडों का अधिग्रहण कर लिया गया है

अकादमिक उपलब्धियां

- चुनौती 2018: सरकारी स्कूल के छात्रों में सीखने की कमियों को दूर करने के लिए अभियान
- शिक्षक दिवस से बाल दिवस तक 'पढ़ने की शतप्रतिशत क्षमता' अभियान में एक लाख से अधिक बच्चों ने पढ़ना सीखा
- पूरी दिल्ली में समुदायों, पार्कों, मैदानों में 1000 'रीडिंग मेले'
- 500 स्कूलों में ग्रीष्मकालीन शिविर (समर कैंप) का आयोजन
- सभी स्कूलों में एक साथ दो मेगा–पीटीएम आयोजित, मेगा–पीटीएम में भारी संख्या में अभिभावकों की सहभागिता

PTM

New Initiative

SUMMER CAMPS

KUCH MASTI KUCH PADHAI

टीचर्स ट्रेनिंग

- 100 प्रिंसिपल्स को लीडरशिप प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए कैंब्रिज युनिवर्सिटी, ब्रिटेन भेजा गया।
- एक अनूठे कार्यक्रम 'मेंटर टीचर' में हमारे 200 सर्वश्रेष्ठ शिक्षक दूसरे शिक्षकों का समर्थन व सहयोग के साथ उनको बढ़ावा दे रहे हैं।
- 100 मेंटर शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए सिंगापुर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भेजा गया।
- 800 प्रिंसिपल्स को नेतृत्व विकास का प्रशिक्षण
- नवीन शिक्षण विधियों पर 20000 से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षण

प्राइवेट स्कूलों पर नकेल

- सरकार ने दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की के मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने पर रोक लगाई। इसके लिए सरकारी भूमि पर बने सभी निजी स्कूलों का ऑडिट किया गया और पहली बार स्कूलों ने अभिभावकों को जमा की गयी बढ़ी फीस लौटाई।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के बच्चों का प्राइवेट स्कूलों में दाखिले के लिए ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम लागू किया, इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के नामांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सकी है।

अंबेडकर विश्वविद्यालय का विस्तार

- कर्मपुरा में अंबेडकर विश्वविद्यालय का नया परिसर खोला गया। स्नातक स्तर पर चार पाठ्यक्रमों की शुरूआत हुई 2100 छात्रों को दो नए कैंपसों में दाखिला दिया गया। वर्ष 2022 तक यहां छात्रों की संख्या 10000 तक जाएगी।
- अगले शैक्षणिक सत्र से लोधी रोड और कराला गांव में दो और नए कैंपस शुरू करने का प्रस्ताव।
- जुलाई 2016 में करमपुरा में नया एयूडी कैंपस शुरू करने से स्नातक स्तर पर 209 दाखिलों की वृद्धि हुई

नए पाठ्यक्रमों की शुरुआत

- डिग्री स्तर के कौशल विकास अवसरों का सृजन करने के लिए प्रौद्योगिकी (पोलीटेक्नीक) के नौ संस्थानों में नए पाठ्यक्रम (बी.वॉक.) की शुरुआत की गई ताकि उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में कुशल युवाओं के लिए प्रवेश का द्वार खुल सकें।
- यह पाठ्यक्रम सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट, मोबाइल कम्यूनिकेशन, ऑटोमोबाइल, प्रिंटिंग और पब्लिशिंग, पावर डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट और कन्सट्रक्शन टेक्नोलॉजी में विशेषज्ञता प्रदान करता है।
- कुल मिलाकर, इस तीन–वर्षीय प्रोग्राम के लिए प्रत्येक बैच में 900 सीटें (3 वर्षों में कुल 2700) तैयार की गई हैं । इन पाठ्यक्रमों को लेकर स्टूडेन्टस में बहुत क्रेज है।

नए आईटीआई

- 1500 युवाओं को कौशल विकास के अवसर प्रदान करने के लिए मंगोलपुरी और नंदनगरी (महिलाओं के लिए) में दो नए आईटीआई और रजोकरी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई है।
- रनहोला, बक्करवाला और छतरपुर में तीन नए आईटीआई तथा बक्करवाला, कादीपुर, सदौड़ा माजरा (बुराड़ी) और मंडोली में चार नए आईओटी का प्रस्ताव योजनाधीन है।
- स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 160 सीटों की वृद्धि के साथ 2015 में दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस ऐंड रिसर्च को अपग्रेड कर पहली भारतीय फार्मास्यूटिकल यूनिवर्सिटी, दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस ऐंड रिसर्च यूनिवर्सिटी क्रियाशील कर दिया गया है।

एनएसआईटी, आईआईआईटी, डीटीयू के विस्तार की योजना

- आईआईआईटी–डी के फेज–2 का निर्माण जून 2017 तक पूरा होने की संभावना है, जिससे छात्रों के दाखिले के लिए1400 अतिरिक्त सीटें 3 उपलब्ध होंगी।
- नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी बनाया जा रहा है और छात्रों की संख्या 4000 से बढ़ाकर 10000 की जा रही है।
- 2000 छात्रों की क्षमता वाला डीटीयू का पूर्वी कैंपस की योजनाबद्ध है। बवाना में डीटीयू का दूसरे चरण दाखिले की (जिससे क्षमता 8000 छात्रों से बढ़कर 12000 हो जाएगी) और एनएसआईटी का दूसरा फेज निर्माणाधीन है। नए जी.बी. पंत टेक्निकल कैंपस की योजना बनाई गई है, जिससे छात्रों के दाखिले की मौजूदा 3000 की क्षमता बढ़कर 7000 हो जाएगी।
- सिंगापुर सरकार के सहयोग से स्थापित विश्व स्तरीय कौशल केंद्र में 2015–16 के दौरान नए पाठ्यक्रम शुरू किए गए है। प्रवेश क्षमता 400 सीटों से बढ़कर 900 हो गई है।

सरकार-उद्योग की सहभागिता

- इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) के साथ सहभागिता में आईटीआई, अरब की सराय में एक प्रशिक्षण केंद्र शुरु किया गया है। यहां पर विभिन्न सरकारी आईटीआई के छात्रों को गैस प्लंबिंग क्षेत्र में प्रशिक्षण मिलेगा।
- सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ सहभागिता में आईटीआई, धीरपुर में एक 'एडवांस्ड रिपेयर एंड स्किल एन्हैंसमेंट ट्रेनिंग ई–प्रोग्राम' शुरू किया गया है।

HEALTH

विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं

- दिल्ली सरकार ने 36 मल्टीस्पेशल्टी अस्पतालों के साथ मजबूत स्वास्थ्य सेवा की ढांचागत संरचना को तैयार किया है जिसमें छह सुपर स्पेशल्टी अस्पताल, ब्लड बैंक और ब्लड स्टोरेज की सुविधाओं वाले 10 अस्पताल तथा ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 69 प्राइवेट अस्पतालों में 731 निःशुल्क बिस्तर सहित 11,000 से अधिक बिस्तर शामिल हैं।

- दिल्ली में 242 ऐलोपैथिक डिस्पेंसरी, 107 आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक (पायलट व नियमित), 23 पोलीक्लीनिक, 58 सीड प्राथमिक शहरी स्वास्थ्य केंद्र (पीयूएचसी), 39 आयुर्वेदिक, 19 यूनानी व 101 होम्योपैथिक डिस्पेंसरी, 43 मोबाइल क्लीनिक, 70 स्कूल हेल्थ क्लीनिक हैं।

- स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का काम 25000 से अधिक डॉक्टर और संबद्ध स्वास्थ्य सहायक कर रहे हैं। सरकार ने स्वास्थ्य सेवा के निवारक और प्रोत्साहक पहलू पर ध्यान बढ़ाया है और स्वास्थ्य के प्रबंधन के प्रति समग्र दृष्टिकोण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाया जा रहा है ताकि बीमारी के बोझ, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके।

स्वास्थ्य सेवा में सुधार

- आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक्स ने दिल्ली में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में उल्लेखनीय सुधार किया है।

- संयुक्त राष्ट्र के भूतपूर्व महासचिव कोफी अन्नान ने मोहल्ला क्लीनिक्स के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा है कि ''दिल्ली के मोहल्ला क्लीनिक भारत में और संभवतः पूरे दक्षिण एशिया में यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज (यूएचसी) के लिए एक आदर्श होने चाहिए'',

The Washington Post

What New Delhi's free clinics can teach America about fixing its broken health care system

By Vivek Wadhwa March 11, 2016

Rupandeep Kaur, 20 weeks pregnant, arrived at a medical clinic looking fatigued and ready to collapse. After being asked her name and address, she was taken to see a physician who reviewed her medical history, asked several questions, and ordered a series of tests including blood and urine. These tests revealed that her fetus was healthy but Kaur had dangerously low hemoglobin and blood pressure levels. The physician, Alka Choudhry, ordered an ambulance to take her to a nearby hospital.

All of this, including the medical tests, happened in 15 minutes at the Peeragarhi Relief Camp in New Delhi, India. The entire process was automated — from check-in, to retrieval of medical records, to testing and analysis and ambulance dispatch. The hospital also received Kaur's medical records electronically. There was no paperwork filled out, no bills sent to the patient or insurance company, no delay of any kind. Yes, it was all free.

The hospital treated Kaur for mineral and protein deficiencies and released her the same day. Had she not received timely treatment, she may have had a miscarriage or lost her life.

This was more efficient and advanced than any clinic I have seen in the West. And Kaur wasn't

the only patient, there were at least a dozen other people who received free medical care and prescriptions in the one hour that I spent at Peeragrahi in early March.

The facility, called the "mohalla" (or people's) clinic, was opened in July 2015 by Delhi's chief minister, Arvind Kejriwal. This is the first of 1,000 clinics that he announced would be opened in India's capital for the millions of people in need. Delhi's health minister Satyendar Jain, who came up with the idea for the clinics, told me he believes that not only will they reduce suffering, but also overall costs — because people will get timely care and not be a burden on hospital emergency rooms.

The technology that made the instant diagnosis possible at Peeragarhi was medical device called the Swasthya Slate. This $600 device, the size of a cake tin, performs 33 common medical tests including blood pressure, blood sugar, heart rate, blood haemoglobin, urine protein and glucose. And it tests for diseases such as malaria, dengue, hepatitis, HIV, and typhoid. Each test only takes a minute or two and the device uploads its data to a cloud-based medical-record management system that can be accessed by the patient.

The Swasthya Slate was developed by Kanav Kahol, who was a biomedical engineer and researcher at Arizona State University's department of biomedical informatics until he became frustrated at the lack of interest by the medical establishment in reducing the cost of diagnostic testing. He worried that billions of people were getting no medical care or substandard care because of the medical industry's motivation in keeping prices high. In 2011, he returned home to New Delhi to develop a solution.

Swasthya Slate Embed Share Play Video5:34

Swasthya Slate is a mobile kit which empowers frontline health workers with usable technology for prevention diagnosis care and referral of diseases. The Swasthya Slate kit was launched in the state of Jammu and Kashmir by the Ministry of Health in 2014. (Swasthya Slate)

Kahol had noted that despite the similarities between medical devices in their computer displays and circuits, their packaging made them unduly complex and difficult for anyone but highly skilled practitioners to use. They were also incredibly expensive — usually costing tens of thousands of dollars each. He believed he could take the same sensors and microfluidics technologies that the expensive medical devices used and integrate them into an open medical platform. And with off-the-shelf computer tablets, cloud computing, and artificial intelligence software, he could simplify the data analysis in a way that minimally-trained front-line workers could understand.

By Jan. 2013, Kahol had built the Swasthya Slate and persuaded the state of Jammu and Kashmir, in Northern India, to allow its use in six underserved districts with a population of 2.1 million people. The device is now in use at 498 clinics there. Focusing on reproductive maternal and child health, the system has been used to provide antenatal care to more than 22,000 mothers. Of these, 277 mothers were diagnosed as high risk and provided timely care. Mothers are getting care in their villages now instead of having to travel to clinics in cities.

A newer version of the Slate, called HealthCube, was tested last month by nine teams of physicians and technology, operations, and marketing experts at Peru's leading hospital, Clinica Internacional. They tested its accuracy against the western equipment that they use, its durability in emergency room and clinical settings, the ability of minimally trained clinicians to use it in rural settings, and its acceptability to patients. Clinica's general manager, Alvaro Chavez Tori, told me in an email that the tests were highly successful and "acceptance of the technology was amazingly high." He sees this technology as a way of helping the millions of people in Peru and Latin America who lack access to quality diagnostics.

The opportunity is bigger than Latin America, however. When it comes to health care, the United States has many of the same problems as the developing world. Despite the Affordable Care Act, 33 million Americans or 10.4 percent of the U.S. population still lacks health insurance. These people are disproportionately poor, black or Hispanic, and 4.5 million are children. As a result, they receive less preventive care and suffer from more serious illness — which are extremely costly to treat. Emergency rooms of hospitals are overwhelmed by uninsured patients seeking basic medical care. And when they have insurance, families are often bankrupted by medical costs.

It may well be time for America to build mohalla clinics in its cities.

MOHALLA CLINICS MODEL TO SCALE UP HEALTHCARE

- Kofi Annan

Kofi Annan, *Chair*
Martti Ahtisaari
Ela Bhatt, *Elder Emeritus*
Lakhdar Brahimi
Gro Harlem Brundtland
Fernando H. Cardoso, *Elder Emeritus*
Jimmy Carter, *Elder Emeritus*
Hina Jilani
Ricardo Lagos
Graça Machel
Mary Robinson
Desmond Tutu, *Elder Emeritus*
Ernesto Zedillo

Honourable Chief Minister Arvind Kejriwal
State of Delhi
Delhi
India

25 January, 2017

Honourable Chief Minister,

I am writing today in my capacity as Chair of The Elders, an organisation of independent global leaders founded by Nelson Mandela. The Elders offer their collective experience to promote peace, justice and human rights worldwide.

The Elders are keen to raise with you an issue of great international importance, which we understand is also a top priority for your government: Universal Health Coverage (UHC). As you may know, UHC is one of the key targets within the new health Sustainable Development Goal. It is achieved when everybody receives the healthcare they need without suffering financial hardship.

Last May, The Elders launched a new initiative to encourage countries to reach UHC as we are convinced that providing universal healthcare, free at the point of delivery, is one of the most important drivers of development. We are aware that your administration has implemented a series of health reforms consistent with the UHC goal. In particular, you have scaled up the provision of universal free health services, most notably in providing free primary healthcare services through your new Mohalla Clinics. We understand that this initiative is proving very successful and we commend you on this impressive achievement.

In the hope that this may be of assistance, we respectfully attach here a memorandum reflecting on your health reforms to date and suggesting some areas where you may wish to develop your programme. Were you to implement these policies, we believe you could further extend health coverage in Delhi and provide further important lessons for other Indian states embarking on their UHC journeys.

From experience elsewhere, including in some of our own countries, the Elders believe that a bold move to advance UHC could bring tremendous health and economic benefits to the people of India. It would also, of course, be likely to prove extremely popular.

In case you require further information or wish to discuss the matter with The Elders, we would be delighted to hear from you.

Please accept, Honourable Chief Minister, the assurances of my highest consideration and esteem.

Kofi Annan
Chair, The Elders

आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक – एक नजर में

आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक्स की कुल संख्या	107 क्लीनिक
2017–18 में एएएमसी के निर्माण के लिए अनुमोदित योजनाओं की कुल संख्या	300
मोहल्ला क्लीनिक्स में ओपीडी मरीजों की कुल संख्या	26 लाख
मोहल्ला क्लीनिक्स में नैदानिक सेवाएं लेने वाले कुल मरीजों की संख्या	1,30,024
नैदानिक परीक्षणों की कुल संख्या	2,60,756

1. नई पहल

- एमबीबीएस कोर्स में 100 सीटों की क्षमता के साथ नए मेडिकल कॉलेज, 'बाबा साहिब अंबेडकर मेडिकल कॉलेज, रोहिणी' चालू हो गया है।

- दिल्ली के 10 सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क मेडिकल और सीटी स्कैन

- सभी मरीजों के लिए निःशुल्क दवाइयां और मेडिकल टेस्ट।

- स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली (एचआईएमएस) एक ऐसी पहल है जिसे सेवाओं को सरल और कारगर बनाने हेतु दिल्ली सरकार के सभी अस्पतालों और डिस्पेंसरियों के लिए शुरू किया गया है। यह प्रक्रिया एक बार मरीज का पंजीकरण कर उसे व्यक्तिगत स्वास्थ्य कार्ड जारी करने से शुरू होती है। पंजीकरण के बाद, मरीज को एक स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाता है तथा परामर्श और लैब जांच आदि के लिए मरीज की जानकारी ऑनलाइन स्टोर की जाती है।

- दिल्ली सरकार के पांच अस्पतालों (एलएनजेपीएच, जीटीबीएच, बीएसएच, डीडीयूएच और एलबीएसएच) की फार्मेसियों को आउटसोर्स करने तथा इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल, सरिता विहार के बाहर एक निःशुल्क जेनेरिक फार्मेसी खोलने की योजना है।

- दिल्ली के निवासियों के लिए युनिवर्सल हेल्थकेयर इंश्योरेंस स्कीम शुरू करने की योजना है। इस स्कीम का लक्ष्य डायग्नॉस्टिक, प्रोसीजर और सर्जरी सहित कैशलेस तरीके से अस्पताल में भरती होने की सुविधा प्रदान करना है।

खुबसूरत लोग
हमेशा स्वस्थ नहीं होते
स्वस्थ लोग हमेशा
खुबसूरत होते है
क्लीनिक

क्लीनिक
INIC

दिल्ली सरकार के अधीन हेल्थ आउटलेट की संख्या

क्र.सं.	हेल्थ आउटलेट का नाम	हेल्थ आउटलेट की संख्या
1	अस्पतालों की संख्या	36
2	डिस्पेंसरियों की संख्या (आयुष सहित)	401
3	आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक्स की संख्या	107
4	पोलीक्लीनिकों की संख्या	23
5	मोबाइल हेल्थ क्लीनिक्स की संख्या	43
6	स्कूल हेल्थ क्लिनिकों की संख्या	70
7	सीड प्राथमिक शहरी स्वास्थ्य केंद्र (पीयूएचसी)	59
	कुल	**739**

2. स्वास्थ्य सेवा के विस्तार के लिए दिल्ली सरकार अस्पतालों और बिस्तरों की संख्या बढ़ाने का प्रयास कर रही है और इसे बढ़ाकर 10000 अतिरिक्त बिस्तर मुहैया कराए जाएंगे।

2013–14 से 2016–17 तक बिस्तरों की संख्या का ट्रेंड

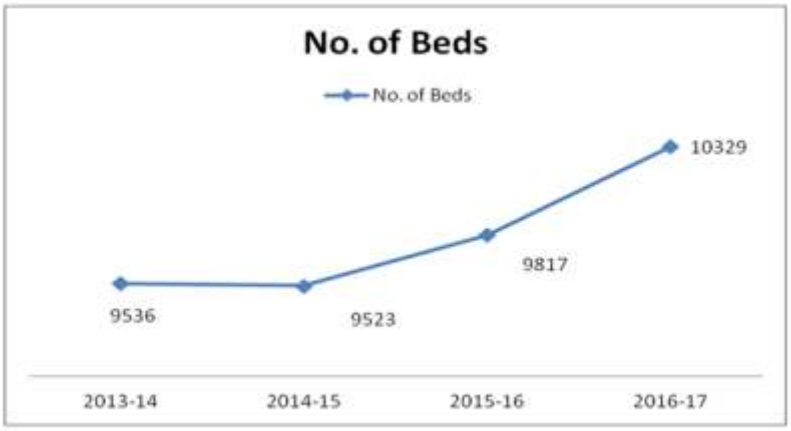

ऊपर दिया हुआ ग्राफ दर्शाता है कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या 2013–14 में 9536, 2014–15 में 9526, 2015–16 में 9817 थी तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान 10329 है जो दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सवाओं में सुधार के प्रयासों की गम्भीरता को दर्शाता है।

3. बिस्तरों की संख्या बढ़ने के साथ ओपीडी में मरीजों की संख्या में वृद्धि

2013–14 से 2015–16 तक दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी में मरीजों की संख्या के ट्रेंड

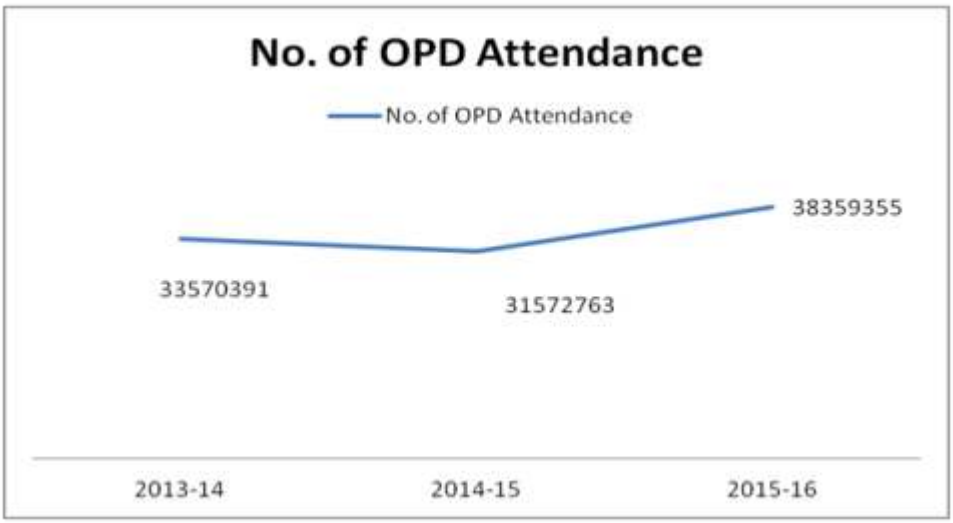

ऊपर दिए हुए ग्राफ से जाहिए है कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी में मरीजों की संख्या 2013–14 में 3570391, 2014–15 में 31572763 और 2015–16 में बढ़कर 38359355 हो गई।

4. आईपीडी में मरीजों की संख्या

2013–14 से 2015–16 तक दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में आईपीडी में मरीजों की संख्या के ट्रेंड

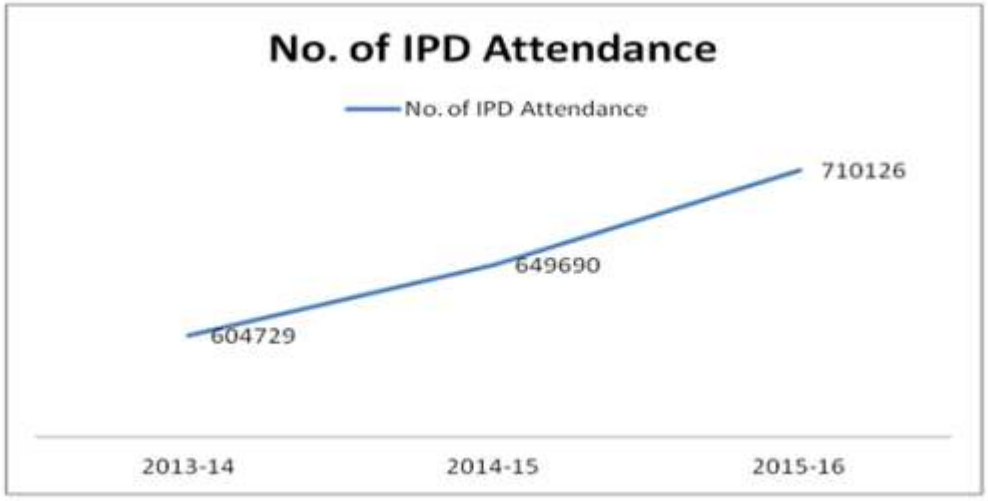

ऊपर दिए गए ग्राफ से पता चलता है कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में आईपीडी में मरीजों की संख्या 2013–14 में 604729, 2014–15 में 649690 और 2015–16 में में बढ़कर 710126 हो गई।

5. दिल्ली सरकार द्वारा ''होम टु हॉस्पिटल केयर'' एंबुलेंस सर्विस स्कीम का शुभारंभ किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत कैट्स एंबुलेंस घर के दरवाजे पर सभी प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी के लिए निःशुल्क एंबुलेंस सेवाएं प्रदान किया जा रहा हैं। 100 सामान्य तथा 10 एडवांस्ड स्टैण्डर्ड सपोर्ट एंबुलेंस की आपूर्ति की जा चुकी है। इन 110 में से, फिलहाल, 72 बीएलएस एंबुलेंस कार्यरत हैं और बाकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के अधीन हैं जो जल्दी ही कार्यरत हो जाएंगी। मॉडल कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है जिसका उद्घाटन दिल्ली के उप–मुख्यमंत्री द्वारा 3 जुलाई, 2016 को किया गया।

6. खाद्य सुरक्षा विभाग खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों को लागू कर दिल्ली के निवासियों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। खाद्य व्यापार ऑपरेटरों (एफबीओ) को वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान लगभग 2367 लाइसेंस और 23233 पजीकरण जारी किए गए हैं।

7. ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने औषधीय नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर सख्त नीति अपनाई है और दोषियों के खिलाफ विभाग कड़ी कार्रवाई कर रहा है। विभाग ने दिल्ली में पहले ही दवाई की 14 दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिए जो नशीली दवाइयां बेचते या स्टॉक करते पाए गए।

दिल्ली जल बोर्ड

- पानी के 12,56,883 घरेलू उपभोक्ताओं ने 20,000 लीटर प्रति माह तक की निःशुल्क जल आपूर्ति का लाभ उठाया जिनके यहां पानी के चालू मीटर के साथ घरेलू पानी कनेक्शन थे। (ये पानी कनेक्शनों की संख्या है, जिन्होंने यह लाभ या तो एक बार उठाया है या जिन्हें उनकी मासिक खपत के आधार पर यह लाभ मिलना जारी है)।

- 01–04–2015 को सक्रिय उपभोक्ताओं की जो संख्या 19.20 लाख थी, वह बढ़कर 21.66 लाख हो गई है तथा इन सभी उपभोक्ताओं की द्विमासिक बिलिंग सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

- जल और सीवर विकास शुल्क जो रु. 494 प्रति वर्ग मीटर था, उसमें भारी कटौती करके रु.100 प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया जिससे बड़ी संख्या में उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं।

- 309 अनधिकृत कालोनियों में नल–जल आपूर्ति मुहैया कराई गई है, इस प्रकार कुल 1797 अनधिकृत कालोनियों में से नल–जल आपूर्ति वाली कालोनियों की संख्या 1103 हो गई है। नल–जल आपूर्ति को सभी 44 पुनर्वास कालोनियों में संवर्धित किया गया है, 820 जे.जे. क्लस्टर दिल्ली जल बोर्ड को सौंप दिए गए हैं। सभी जे.जे. क्लस्टरों के पास सार्वजनिक पानी के नल और पानी के टैंकरों के माध्यम से पेयजल की सुविधा उपलब्ध करायी गई है।

- शहर में पानी की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए, गर्मी के मौसम में तकरीबन 900 एमजीडी पेयजल का अधिकतम उत्पादन हासिल किया गया है।

- जल अभाव वाले क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए, ट्यूब वैल, वॉटर एटीएम की स्थापना के साथ–साथ 700 टैंकरों के मौजूदा बेड़े में स्टेनलेस स्टील के 250 नए पानी के टैंकर शामिल किए गए हैं।

- वेब आधारित ऑनलाइन टैंकर मॉनिटरिंग प्रणाली को सुदृढ़ बनाया गया है ताकि लोग अपने मोहल्लों में आने वाले टैंकरों का और उनमें आने वाली पानी की मात्रा का पता लगा सकें।

- 2016–17 के लिए पानी की 350 किलोमीटर नई लाइनें बिछाने के लक्ष्य में से नवंबर 2016 तक 240 किलोमीटर की पानी की नई लाइनें बिछाई जा चुकी हैं तथा वितरण नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए दिल्ली के विभिन्न जिलों में 70 किलोमीटर की पुरानी/जीर्णशीर्ण/क्षतिग्रस्त/लीक हो रही पानी लाइनों को बदला गया।

- द्वारका और बवाना में क्रमशः 50 और 20 एमजीडी क्षमता के दो जल उपचार संयंत्र चालू किए गए हैं जिनसे लगभग 20 लाख लोगों को लाभ होगा। हरियाणा सरकार के साथ समस्याओं का हल निकालते हुए ओखला स्थित जल उपचार संयंत्र की क्षमता 10 एमजीडी से बढ़ाकर 20 एमजीडी कर दी गई है।

- पूरी दिल्ली में कई नए भूमिगत जलाशयों और बूस्टर पंपिंग स्टेशनों को चालू किया गया है जिनसे 25–30 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं।

- उपभोक्ताओं की शिकायतों को हल करने के लिए, सितंबर–अक्टूबर 2016 में पांच जन शिकायत कैंप आयोजित किए गए थे, जिनमें 1898 शिकायतें प्राप्त की गईं और उन्हें हल किया गया।

सीवरेज:

- 6 सीवरेज उपचार संयंत्रों को चालू करने से सीवरेज उपचार क्षमता बढ़कर 604 एमजीडी हो गई है। सीवरेज उपचार का प्रयोग 370 एमजीडी से बढ़कर 455 एमजीडी हो गया है।

- दिल्ली में 200 किलोमीटर ट्रंक सीवर नेटवर्क के साथ 7700 किलोमीटर का सीवर नेटवर्क है। 135 शहरी गांवों में से, 130 गांवों को सीवरेज सुविधाएं प्रदान की गई हैं। इसके अलावा, 189 ग्रामीण गांवों में से 45 गांवों में सीवरेज सुविधाएं प्रदान करने का कार्य पूरा कर लिया गया है।

- दिल्ली गेट में 15 एमजीडी क्षमता का सीवरेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) और यमुना विहार में 25 एमजीडी क्षमता का सीवरेज उपचार संयंत्र चालू किया गया है।

- नदी जल की गुणवत्ता में सुधार के लिए, सभी प्रस्तावित नए एसटीपी की स्थापना अत्याधुनिक तकनीक के साथ की जा रही है ताकि उपचार के उच्चतर गुणवत्ता मानकों को हासिल किया जा सके, यानी की BOD<10 और SS<10 पीपीएम

- यमुना की सफाई के लिए, इंटरसेप्टर सीवर की अभिनव परियोजना 85% तक पूरी कर ली गई है और लगभग 50 एमजीडी अपशिष्ट जल प्रवाह को नालियों से अवरोधित किया और अब उसे सीवरेज उपचार संयंत्र में उपचारित किया जा रहा है।

- 89 एमजीडी उपचारित सहायक पानी का इस्तेमाल सिंचाई, बागवानी के लिए और साथ ही विद्युत संयंत्रों में आपूर्ति के लिए भी किया जा रहा है।

- सीवरेज मास्टर प्लान 2031 का कार्य शुरू कर दिया गया है।

- कॉरनेशन पिलर के पास 70 एमजीडी के अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र के निर्माण का कार्य सितंबर 2016 में शुरू हो गया है और 30 महीनों में इसके पूरा होने का प्रस्ताव है।

दिल्ली जल बोर्ड का राजस्व संग्रह

1. राजस्व संग्रह

2014–15 (रु. करोड़ में)	रू 1219.49
2015–16 (रु. करोड़ में)	रू 1549.94
2016–17 (28.12.16 तक) (रु. करोड़ में)	रू 869.13

2. पानी के कनेक्शनों की संख्या

31.03.2015 तक	2141059
28.12.2016 तक	2474624

3. वर्ष 2015–16 और 2016–17 के दौरान जल एवं सीवर विकास शुल्क की दर में वृद्धि नहीं की गई।
4. निम्नलिखित छूट योजनाएं शुरू की गईं:

   क. बकाया राशि में स्लैब के आधार पर रियायत के साथ–साथ घरेलू उपभोक्ताओं के लिए विलंबित भुगतान सरचार्ज पर 100% छूट।
   ख. वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए विलंबित भुगतान सरचार्ज पर 100% छूट।
   ग. अधिसूचना की तिथि से अनधिकृत कालोनियों के लिए जल एवं सीवर विकास शुल्क में 80% की कटौती।
   घ. अनधिकृत पानी कनेक्शन को नियमित करने के लिए उदारीकृत योजना। इससे गैर–राजस्व जल (एनआरडब्ल्यू) घटेगा और बिलिंग नेट बढ़ेगा।

5. जल बोर्ड के इतिहास में पहली बार, एक बिलिंग चक्र में 19 लाख से अधिक पानी के बिल बनाए गए।

6. एक मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई जिससे उपभोक्ता खुद ही बिल जनरेट करके भुगतान कर सकता है।

7. कैशलेस लेन–देन के लिए सभी जोनल कैश काउंटरों में पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनें लगाई गईं। किसी भी तरह की नेटवर्क कनेक्टिविटी समस्या आदि से निपटने के लिए विभिन्न सेवा प्रदाताओं की 02 पीओएस मशीनों का प्रावधान किया गया है।

8. वाणिज्यिक/औद्योगिक कनेक्शनों के लिए अवसंरचना शुल्क खत्म कर दिया गया।

सस्ती बिजली–24X7

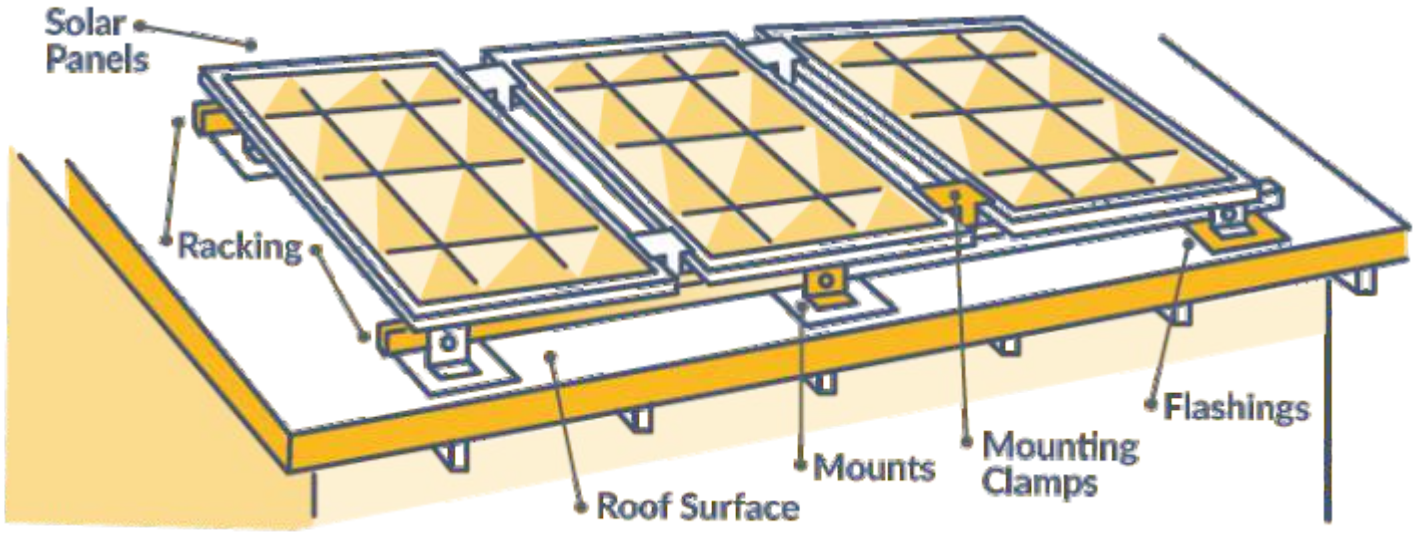

- पिछले दो वर्षों के दौरान बिजली के दरों में किसी भी तरह की बढ़ोत्तरी नहीं हुई।
- सरकार द्वारा मार्च 2015 से राजधानी दिल्ली के घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 400 यूनिट तक बिजली की खपत पर 50% की सब्सिडी प्रदान की जा रही है।
- बिजली सब्सिडीके मद में वर्ष 2016–17 के लिए 1600 करोड़ रुपये के बजट का आवंटन किया गया है। जबकि वर्ष 2015 में 1440 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी।
- बिजली कटौती की शिकायतों के निवारण के लिए 24X7 कॉल सेंटर की स्थापना की गई है। डिसकॉम को यह सुनिश्चत करने को कहा गया है कि अनावश्यक बिजली कटौती नहीं की जाए और यदि आवश्यक हो तो भी 1 घंटे से अधिक अवधि के लिए कटौती ना करें।
- बिजली विवाद समाधान स्कीम– काफी समय से लंबित उपभोक्ता शिकायतों और विवादों को हल करने के लिए सरकार ने जनता के हित में बिजली विवाद समाधान स्कीम शुरु किये हैं। इस योजना के माध्यम से लगभग 35,000 उपभोक्ता सीधे तौर पर लाभान्वित हुए हैं।

- ऊर्जा सक्षम एलईडी बल्ब/स्ट्रीट लाइट– सभी उपभोक्ताओं को 93 रुपये प्रति बल्ब की दर से चार एलईडी बल्ब मुहैया कराए जा रहे है। लगभग 65 लाख एलईडी बल्ब उपभोक्ताओं को वितरित किए जा चुके है।

- लगभग 1.32 लाख एलईडी स्ट्रीट लाइट दिल्ली में लगाई गई हैं।

- अंतरराज्यीय ट्रान्समिसन प्रणाली (आईएसटीएस)– आईएसटीएस योजना के तहत पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा लगभग 3000 करोड़ रुपये की लागत से तुगलकाबाद, द्वारका और महारानी बाग में 400 केवी के सब स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। जिससे वितरण प्रणाली में सुधार होगा और दिल्ली के उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपुर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।

- दिल्ली सरकार द्वारा सोलर रूफ टॉप पॉलिसी लागू की गई है। इसमें ग्रुप नेट मीटरिंग, वर्चुअल नेट मीटरिंग, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन और 200 किलोवॉट तक की क्षमता वाले सौर बिजली संयंत्र को विद्युत निरीक्षक द्वारा निरीक्षण से छूट जैसी कई सुविधाएं हैं। इस पॉलिसी से हरित ऊर्जा सहित बिजली की उपलब्धता बढ़ेगी।

- सोलर रूफ टॉप पॉलिसी के तहत सरकारी भवन की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। अस्पतालों, विश्वविद्यालयों, पम्प हाउसों, न्यायालयों आदि जैसी सरकारी एजेंसियो के छतों का सर्वेक्षण और अध्ययन किए गए है। इन सरकारी भवनों में सोलर प्लान्ट लगाने का कार्य आरम्भ हो चुका है।

- दिल्ली में नेट मीटरिंग के तहत करीब 200 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए है।

- सरकार द्वारा दिल्ली सरकार की इमारतों की स्टार रेटिंग और एनर्जी ऑडिट की शुरुआत कर दी गई है।

- सर्वश्रेष्ठ ट्रांसमिशन यूटिलिटी अवार्ड – दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड को बेहतर बिजली सेवा उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2016 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पावर ट्रांसमिशन यूटिलिटी अवार्ड से नवाजा गया।

- विद्युत उत्पादन क्षेत्र में दूसरा स्थान–राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण 2016 के तहत दिल्ली सरकार की विद्युत उत्पादन कंपनी पीपीसीएल को वर्ष 2016 कादेश भर में दूसरा सर्वश्रेष्ठ विद्युत उत्पादन कंपनी का पुरस्कार मिला।

DUSIB

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीएसयूआईबी)

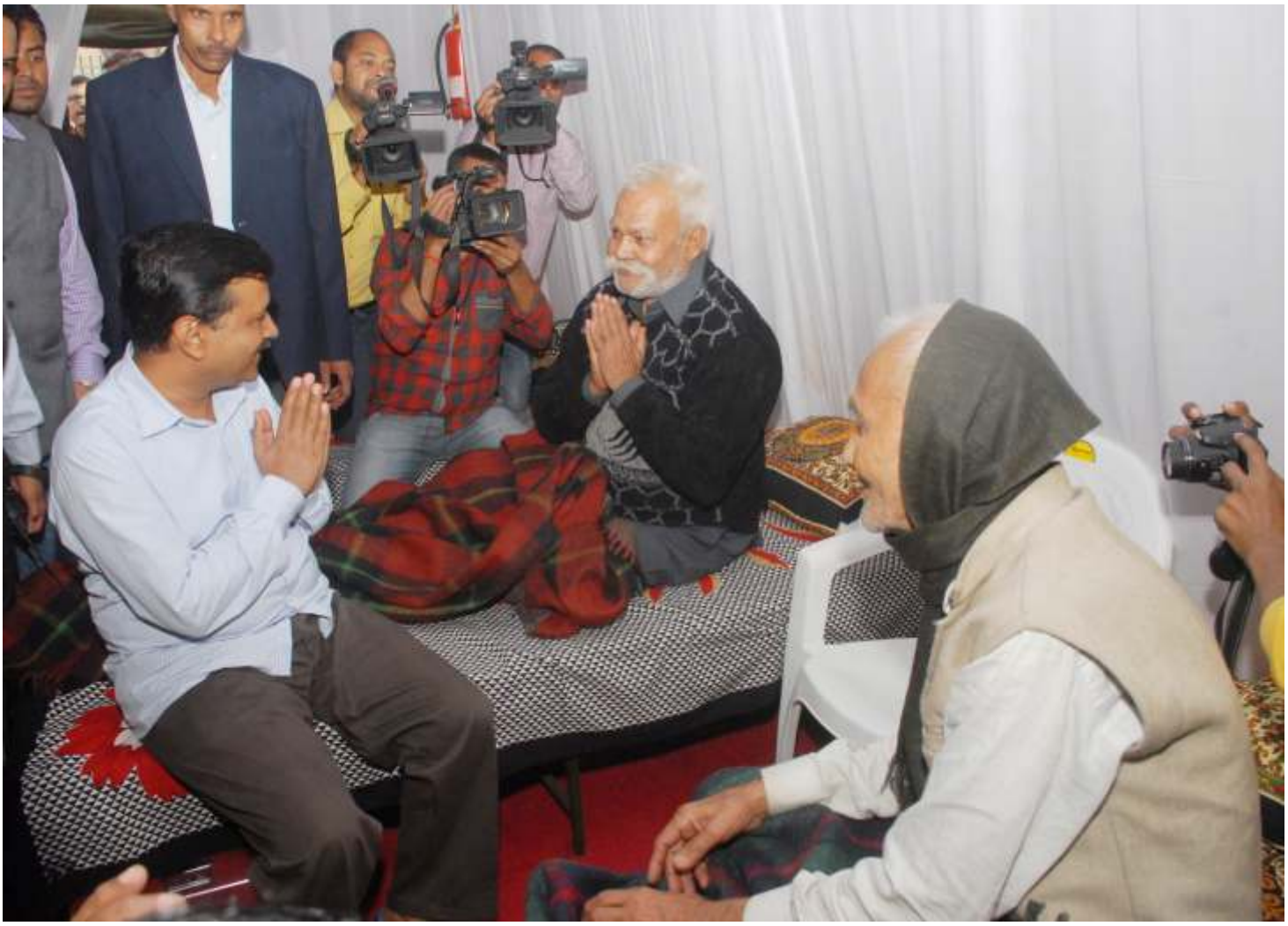

रैन बसेरा

- दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड राजधानी में आधारभूत सुविधाओं से लैस 197 रैनबसेरे चला रहा है जिनमें 16,174 जरूरतमंद व्यक्ति रह सकते हैं।
- कुल 197 रैन बसेरों में से 52 रैन बसेरों का संचालन विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों, दिव्यांग लोगों के परिवारों और नशीली दवाओं के सेवन करने वाले व्यक्तियों के लिये किया जा रहा है।
- सर्दियों में बेघरों के बचाव के लिये 23 बचाव दलों को वाहन और पर्याप्त संख्या में व्यक्तियों के साथ तैनात किया गया है।

- बेघर व्यक्तियों की शिकायतों और बेघरों की सूचना देने के लिए 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। शिकायतों को जानने और उनके निवारण के लिए रात्रि स्थल शिकायत प्रबंधन प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है।

- दिल्ली में बेघरों के बारे में पता लगाने और उन्हें बचाने के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन (App) भी बनाया गया है।

क्रम संख्या	रैन बसेरों के प्रकार	संख्या		व्यक्तियों के रहने की क्षमता	
		2015-16	2016-17	2015-16	2016-17
1	स्थायी	84	81	9359	9299
2	पोर्टा केबिन	114	115	6979	6995
3	टेंट	47	65	2400	3280
4	सब–वे	-	2	-	2000
	कुल	245	263	18738	21574

झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास योजना के अंतर्गत लोगों का पुर्नवास

पिछले दो वर्षों में सुधार बोर्ड ने ज्वाला पुरी, कीर्ति नगर, पंजाबी बाग, जनपथ, और झारखंड भवन की विभिन्न झुग्गी बस्तियों में रहने वाले 717 लोगों व्यक्तियों को फ्लैट दिए हैं।

सामुदायिक शौचालय :

बड़े पैमाने पर खुले में शौच की आदत को खत्म करने के लिए, सुधार बोर्ड जेजे बस्तियों में 'पे ऐंड यूज' जन सुविधा परिसर मुहैया करवा रहा है जिनमें शौचालय और स्नानघर हैं।

- 957 डब्ल्यूसी सीटों वाले 34 नए शौचालयों का पुनःनिर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया है।
- 3318 डब्ल्यूसी सीटों वाले 109 जन सुविधा परिसरों का निर्माण कार्य प्रगति पर ।
- 1760 डब्ल्यूसी सीटों वाले 45 शौचालय परिसरों का निर्माण इस वर्ष पूरा होना प्रस्तावित है।

दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कदम

ऑड-ईवन स्कीम

दिल्ली में भारी प्रदूषण और ट्रैफिक जाम को देखते हुए, अन्य प्रयासो के अलावा, दिल्ली सरकार ने 01 जनवरी से 15 जनवरी 2016 तक तथा 15 से 30 अप्रैल 2016 तक, दो बार 'ऑड–ईवन स्कीम' लागू की। इस स्कीम के अंतर्गत चार–पहिया निजी वाहनों को उनके सम–विषम (ऑड–ईवन) रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर, एक–एक दिन छोड़कर दिल्ली की सड़कों पर चलने की अनुमति थी। इस स्कीम को दुनिया भर से व्यापक सराहना मिली।

कार फ्री डे

दिल्ली सरकार ने 22 अक्टूबर 2015 को पहली बार "कार–फ्री डे" घोषित किया। इस दिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद एक साइकिल रैली की अगुवाई की जिसमें 1000 से अधिक साइकिल सवारों ने हिस्सा लिया। इसने लोगों को सार्वजनिक वाहनों के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित किया। पहले 'कार फ्री डे' का दायरा लाल किले से भगवान दास रोड तक था।

दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक परिवहन सेवा के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के लिए तीन महीनों तक अलग–अलग क्षेत्रों में 'कार–फ्री डे' का आयोजन किया। यह उन कई उपायों में से एक है जो शहर के वायु प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करेगा।

वायु प्रदूषण नियंत्रण कार्य योजना

सरकार ने दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को काबू में करने के लिए निम्नलिखित आपातकालीन कदम उठाए हैं–

1. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन (बीटीपीएस) की सभी इकाइयों को बंद किया गया।
2. बीटीपीएस से फ्लाई–ऐश उठाने पर तत्काल रोक और फ्लाई ऐश स्टोरेज पर पानी का छिड़काव।
3. सड़कों पर झाड़ू लगाने से पहले पानी का छिड़काव।
4. अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली में सभी क्षमताओं के डीजल जेनसेट के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है।
5. पटाखों पर प्रतिबंध (धार्मिक समारोहों को छोड़कर)
6. परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस ने सीमाओं पर और दिल्ली के भीतर कार्रवाइयाँ तेज की है, जैसे ओवरलोडेड ट्रकों के प्रवेश पर रोक, ऐसे ट्रकों के प्रवेश पर रोक जिनका गंतव्य दिल्ली नहीं है, उन वाहनों के खिलाफ कार्रवाई जिनके पास वैध पीयूसीसी नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई। बिना ढके निर्माण सामग्री ले जाने वाले ट्रकों के खिलाफ कार्रवाई।
7. 7 नवंबर 2016 से 14 नवंबर 2016 तक दिल्ली में सभी निर्माण, तोड़फोड़ की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया।
8. डीपीसीसी, एसडीएम और पुलिस के अधिकारियों के विशेष दल बनाकर कूड़ा, सूखी पत्तियाँ जलाने के खिलाफ कार्रवाई।
9. कूड़ा, सूखी पत्तियाँ जलाने की कंप्यूटर ऐप्लिकेशन आधारित मॉनिटरिंग।
10. सैनिटरी लैंडफिल साइटों में आग नियंत्रित करने के लिए सभी पालिका निकायों को निर्देश।

- दिवाली के दौरान, सरकार ने स्कूल/कॉलेज के इको क्लबों, आरडब्ल्यूए, एमटीए आदि के समर्थन और सहयोग से "पटाखों को ना कहें" कैंपेन शुरू किया । आयातित और अवैध पटाखों की बिक्री को रोकने के लिए एसडीएम और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के सदस्यो से मिलकर बने 12 टीमों का गठन किया गया।
- शहर भर में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियानों के माध्यम से पिछले एक वर्ष में दिल्ली के ग्रीन कवर में 0.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। शहर के विभिन्न हिस्सों में स्थानीय माननीय एमएलए, आरडब्ल्यूए आदि द्वारा दिल्ली पार्क ऐंड गार्डन सोसायटी, वन विभाग की सहायता से वृक्षारोपण अभियान चलाए जा रहे हैं।

बैटरी चालित वाहनों को बढ़ावा

गैर–प्रदूषणकारी ई–वाहनों को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से, सरकार ने दुपहिया वाहनों, चार–पहिया वाहनों और साथ ही ई–रिक्शा जैसे विभिन्न प्रकार के ई–वाहन खरीदने पर सब्सिडी स्कीम की घोषणा की है। परिवहन विभाग द्वारा अधिकृत और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पंजीकृत बैटरी चालित ई–रिक्शा मालिक को रु. 30,000 की एक बारगी निर्धारित सब्सिडी दी जाती है।

खुले में अपशिष्ट पदार्थ-कचरा जलाने वाले लोगों की मॉनिटरिंग और उनके खिलाफ कार्रवाई

I कचरा– अपशिष्ट पदार्थ, पत्तियाँ जलाने को रोकने के लिए, डीपीसीसी ने "डेल्ही पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी" के नाम से एक फेसबुक अकाउंट खोला है और साथ ही मोबाइल नंबर 9717593574 के साथ एक व्हाट्सऐप अकाउंट भी शुरू किया गया है।

ii एसडीएम, तहसीलदारों, राजस्व विभाग को उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है।

iii सूखी पत्तियाँ,कचरा,प्लास्टिक इत्यादि जलाने पर रोक लगाने के लिए एमसीडी, डीडीए को निर्देशित किया गया है कि यदि किसी भी प्रकार का उल्लंघन पाया गया तो संबद्ध एस.ओ. (बागवानी) और सैनिटेशन इंस्पेक्टर को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

iv खुले में पत्तियाँ, कचरा, प्लास्टिक, रबड़ आदि जलाने पर रोक लगाने के लिए और निर्माण साइटों पर धूल नियंत्रण उपाय करने के लिए हितधारक विभागों, एजेंसियों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें बुलाई गई हैं।

धूल नियंत्रण उपायों का उल्लंघन करने वालों की मॉनिटरिंग और उनके खिलाफ कार्रवाई

सरकार ने निर्माण परियोजना एजेंसियों/लोगों पर धूल नियंत्रण उपाय लागू करने के माध्यम से वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है।

I. माननीय राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के अनुसार एजेंसियों/लोगों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। सभी स्थानीय निकायों और डीडीए को कहा गया है कि वे सामान्य रूप से आम जनता को तथा विशेष रूप से उन मालिकों और बिल्डरों को धूल नियंत्रण उपायों से अवगत कराएँ जिन्होंने अपनी बिल्डिंग के प्लान को मंजूर करवा लिया है।

ii. डीपीसीसी ने उन निर्माण परियोजनाओं पर जुर्माना लगाया है जो पर्यावरण नियमों का उल्लंघन कर रहें है।

जल प्रदूषण रोकने के उपाय

विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में 1750 बहिरूस्राव उपचार संयंत्र (ईटीपी) संस्थापित हैं। डीपीसीसी नियमित रूप से 22 स्थानों पर 40 मल–जल उपचार संयंत्रों (एसटीपी) की निगरानी कर रहा है। वर्तमान में एसटीपी की क्षमता 684.72 एमजीडी है। इन एसटीपी में क्षमता उपयोग की दर लगभग 64 प्रतिशत है। डीपीसीसी निममित रूप से यमुना नदी, 24 नालों, सीईटीपी और एसटीपी के पानी की गुणवत्ता की निगरानी करता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जल स्त्रोतों का प्रबंधन

पर्यावरण विभाग के अंतर्गत दिल्ली पार्क्स ऐंड गार्डन्स सोसायटी (डीपीजीएस) दिल्ली में अलग–अलग सरकारी एजेंसियों के साथ लगभग 900 जल स्रोतों के प्रबंधन और विकास को समायोजित करती है।

दिल्ली पार्क्स ऐंड गार्डन्स सोसायटी (डीपीजीएस) ठोस अपशिष्ट की डंपिंग से यमुना के बाढ़ के मैदानों की सफाई कर तथा यमुना फ्लड बैंकों को उनके मूल रूप में वापस लाकर माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित करती है।

दिल्ली में अपशिष्ट संचालन और प्रबंधन

खतरनाक अपशिष्ट

माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के ओ.ए. संख्या 305/2013 के निर्देशों के अनुपालन में, उत्तरी एमसीडी ने दिल्ली के खतरनाक अपशिष्ट के निपटान के लिए एक टीएसडीएफ की स्थापना के उद्देश्य से पर्यावरण विभाग, दिल्ली सरकार को निःशुल्क उपयोग के लिए बवाना सैनिटरी लैंड फिल (एसएलएफ) साइट के बाहर 14 एकड़ भूमि सौंपी है ।

इलेक्ट्रॉनिक कचरा

डीपीसीसी ने दिल्ली में 28 ई–कचरा संग्रहण केंद्रों और 65 उत्पादकों को अधिकृत किया है।

बायोमेडिकल कचरा

अभी तक यथा संशोधित बायोमेडिकल कचरा (प्रबंधन और संचालन) नियम, 1998 के कारगर प्रबंधन के लिए दिल्ली में 2 भस्मक, 3 ऑटोक्लेव और 4 श्रेडर मशीनें लगी हुई हैं। करीब 3800 स्वास्थ्य सेवा इकाइयों से ऐसा कचरा इकट्ठा करने और उपचारित करने के लिए दो निजी ऑपरेटर लगे हुए हैं।

शहर के विभिन्न प्रदूषण कारकों का वार्षिक औसत

	SO2	NO2	O3	NH3
2014	17	79	57	39
2015	18	73	60	39
2016	20	70	48	40

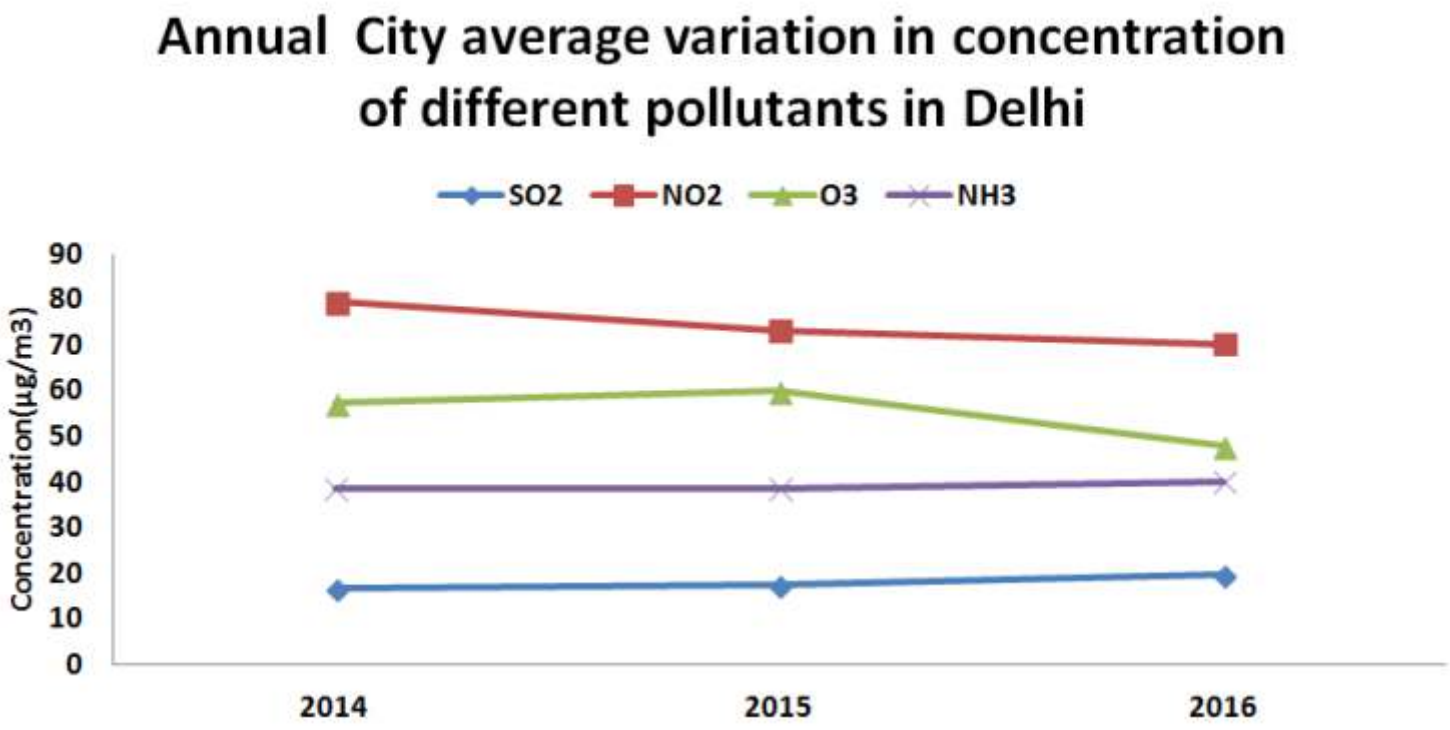

परिवहन सुधार

- 11 बस डिपो का निर्माण
- क्लस्टर बस स्कीम के अंतर्गत 200 बसों का नया बेड़ा
- 10,000 नए ऑटो परमिट
- टैक्सी और ऑटो रिक्शा सेवा को सुगम बनाने के लिए पूछो ऐप
- 116 किलोमीटर के आठ कॉरिडोर वाले मेट्रो फेज 4 के प्लान की स्वीकृति
- ई–टिकटिंग की शुरुआत
- ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस

पब्लिक ट्रांसपोर्ट के विकास के लिए बस डिपो का निर्माण

किसी भी मेगा–सिटी के लिए सार्वजनिक परिवहन एक आधारशिला होता है और दिल्ली सरकार अपने डीटीसी बेड़े को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है जो हमारे सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क का आधार है। बहरहाल, बस डिपो के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध न हो पाने के कारण, बसों की संख्या में इजाफा नहीं किया जा रहा था। सरकार ने इस मामले को प्राथमिकता पर लिया और अब तकरीबन 415 करोड़ रु.की लागत से 11 बस डिपो बनकर तैयार होने के विभिन्न चरणों में हैं। इन प्रयासों के कारण, सरकार अब लगभग 3000 नई बसों के टेंडर जारी करने की ओर अग्रसर है। बस डिपो के नाम इस प्रकार हैं:–

1. ढिचाऊं कलां, दक्षिण–पश्चिम जिला (5 एकड़)
2. द्वारका सेक्टर–22(10 एकड़)
3. बवाना सेक्टर–1(3.75 एकड़)
4. रेवला खानपुर, दक्षिण–पश्चिम जिला (4 एकड़)
5. खरखरी नाहर, दक्षिण–पश्चिम जिला (5 एकड़)
6. रानी खेड़ा 1–रोहिणी फेज–5 (6.67 एकड़)
7. रानी खेड़ा 2–रोहिणी फेज–5 (6 एकड़)
8. रानी खेड़ा 3–रोहिणी फेज–5 (6 एकड़)
9. नरेला (10 एकड़)
10. पूर्वी विनोद नगर (4.8 एकड़)
11. बवाना सेक्टर–5(5 एकड़)

प्राइवेट स्टेज कैरिज संचालनों का पुनर्गठन – क्लस्टर बसों का प्रवेश

असुरक्षित मानी जाने वाली ब्लू लाइन बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाने का काम पूरा हो चुका है। उनके स्थान पर सरकार ने क्लस्टर बस सिस्टम के अंतर्गत नई बसों की संख्या में वृद्धि करने की शुरुआत कर दी है। इन नई योजना के तहत 11,000 बसों के समेकित बेड़े में से, डीटीसी प्रत्येक क्लस्टर रूट में 50 फीसदी बसों का संचालन करेगा और बाकियों का संचालन निजी कंपनियों द्वारा किया जाएगा।

पिछले वर्ष के दौरान क्लस्टर बस स्कीम के तहत 200 से अधिक बसों को शामिल किया गया , जिससे इस स्कीम के अंतर्गत आने वाली बसों की कुल संख्या 1700 हो गई है। मार्च 2017 तक इस स्कीम के अंतर्गत और 225 और बसों को शामिल किया जाएगा।

महिला सुरक्षा और लैंगिक संवेदनशीलता

- डीटीसी द्वारा बस कर्मियों के लिए शुरू किए गए विशेष लैंगिक संवेदनशीलता से सम्बन्धित कार्यक्रम को महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए नियमित रूप से संचालित किया जा रहा है।

- महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए डीटीसी बसों में (शाम और रात की शिफ्ट में)1269 होमगार्ड, 1818 सिविल डिफेंस वॉलंटियर और 170 अतिरिक्त स्टाफ को 'मार्शल' के रूप में तैनात किया गया है।

- स्टेज कैरिज बसों और मेट्रो फीडर बसों में महिलाओं के लिए 25 फीसदी सीटें आरक्षित की गई हैं। मेट्रो रेल में प्रत्येक कंपार्टमेंट में 4 सीटें महिलाओं के लिए तथा 8 सीटें विकलांगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरक्षित हैं।

- 26 रूटों पर व्यस्ततम समय के दौरान लेडीज स्पेशल बसें चलाई जा रही हैं।

- डीटीसी बसों में सीसीटीवी कैमराः 200 लो फ्लोर बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रारंभिक परियोजना पूरी हो गई है। सरकार ने सभी डीटीसी और क्लस्टर बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला किया है।

ऑटो परमिट

दिल्ली सरकार सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के अंतर्गत लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए प्रतिबद्ध है जिससे यात्रियों को उनके मौहल्ले तक परिवहन सुविधा उपलब्ध हो सके। दिल्ली में ऑटो रिक्शा का यात्रियों के लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी में प्रमुख भूमिका हैं। सरकार ने एलओआईस्कीम स्वीकृत की है और फलस्वरूप इस वर्ष 10,000 नए ऑटो परमिट जारी किए गये है।

दिल्ली मेट्रो फेज–४

क्र. सं.	कॉरिडोर	लंबाई (कि.मी.)	पूंजी लागत (करोड़ रु. में)
1	रिठाला–बवाना–रिठाला	21.73	7836
2	जनक पुरी पश्चिम से आर.के. आश्रम	28.92	14522
3	मुकुंदपुर से मौजपुर	12.54	4476
4	इंद्रलोक से इंद्रप्रस्था	12.58	8421
5	एरो सिटी से तुगलकाबाद	20.20	11330
6	लाजपत नगर से साकेत जी–ब्लॉक	07.96	3018
	कुल	**103.93**	**49603**

इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग सिस्टम

दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुचारू, सुगम और पारदर्शी बनाने के प्रयास के तहत स्टेज कैरिज बसों में इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीनों की शुरुआत की गई है। सभी क्लस्टर बसों में अब इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीनें हैं और डीटीसी तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ रहा है ताकि डीटीसी की सभी बसों में इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीनें लगाई जा सके।

ऑनलाइन नागरिक केंद्रित सेवाएं

परिवहन विभाग द्वारा प्रदान की जा रही सभी सेवाओं को ऑनलाइन कर नागरिकों को सशक्त बनाने की दिशा में दिल्ली सरकार ने गम्भीर प्रयास किए है। इससे कार्य में विभाग का हस्तक्षेप कम होगा और नागरिक आराम से घर बैठे सेवाओं लाभ उठा सकेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अपॉइंटमेंट और फीस भरने की ऑनलाइन सुविधा पहले ही शुरू की जा चुकी है ताकि प्रकिया सुगम हो और समय की बचत भी हो सके। दिल्ली में वाहन सॉफ्टवेयर को कार्यान्वित कर दिया गया है जिसमें डीलर की ओर से निजी वाहनों का पंजीकरण, आरसी जारी किया जाना, डुप्लीकेट आरसी, अस्थायी पंजीकरण, स्वामित्व का हस्तांतरण आदि सेवाएं शामिल हैं।

''पूछ ओ'' ऐप

सरकार ने शहर में टैक्सी और ऑटो–रिक्शा सेवाओं को सुगम बनाने के लिए ''पूछ ओ'' लॉन्च की है। यह सेवा उन ऑटो–रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों को एक कॉमन सर्वर से जुड़ने में सक्षम बनाएगी जिनके वाहनों में जीपीएस लगा हुआ है। उसके बाद यात्री अपने स्मार्टफोन के जरिए टैक्सी या ऑटोरिक्शा घर बैठे बुक कर सकेंगे। ऑटो फाइंडर ऑपरेशन के साथ–साथ, यात्रियों की सुविधा के लिए यह ऐप किराया भी बताएगी और यातायात की लाइव अपडेट भी देगी।

फैंसी नंबरों की ई–नीलामी

दिल्ली के लोगों को परिवहन सेवा में सहूलियत और पारदर्शिता के लिए सरकार ने वाहनों के फैंसी नंबरों की सेवा को ऑनलाइन किया है। इच्छुक आवेदक अपने घर बैठे ही अपनी पसंद के नंबर के लिए बोली लगा सकते हैं। ये पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है । पसंद के 140 पंजीकरण अंकों की ई–नीलामी का शुभारंभ 18 सितंबर, 2014 को दिल्ली के माननीय उप–राज्यपाल द्वारा किया गया था। दिसंबर 2016 तक नीलामी के 70 राउंड पूरे हो चुके हैं, जिनसे सरकार को लगभग 21 करोड़ की राजस्व की प्राप्ति हुई है।

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी):

भारत में पहली बार 'अनअटेंडेड ट्रेन ऑपरेशन' प्रणाली युक्त ट्रेन के ट्रायल रन का आरंभ 17 मई को किया गया। यह ट्रायल ट्रेन मुकुंदपुर डिपो से लेकर मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन तक चलाई गई जो मेट्रो के तीसरे चरण के मजलिस पार्क–शिव विहार मेट्रो कॉरिडोर (पिंक लाइन) का हिस्सा है।

- आईटीओ से कश्मीरी गेट के बीच (5.17 कि.मी., वॉयलेट लाइन) तथा बॉटेनिकल गार्डन से कालकाजी मंदिर के बीच (13 कि.मी., मैजेंटा लाइन) और जनकपुरी वेस्ट से टर्मिनल 1 आईजीआई एयरपोर्ट के बीच (10 कि.मी., मैजेंटा लाइन) सिविल कार्यों के पूरा होने के बाद इन मार्गों पर ट्रायल रन शुरू किया गया।
- जनकपुरी पश्चिम–टर्मिनल 1 आईजीआई एयरपोर्ट सेक्शन पर, ट्रायल शुरू करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, हाल ही में आवश्यक सूक्ष्मता के साथ क्रेन और ट्रेलरों का इस्तेमाल कर सदर बाजार कैंट स्टेशन के पार पूरी छः डिब्बों की ट्रेन को सावधानीपूर्वक पटरी पर उतारा गया, जिससे न तो ट्रेन को और न ही सिविल संरचना को कोई नुकसान पहुंचा।

वर्तमान में, रोजाना औसतन लगभग 28 लाख लोग मेट्रो से सफर करते हैं। 17 अगस्त को, पहली बार दिन भर में 33 लाख लोगों ने मेट्रो से सफर किया। उससे कुछ दिन पहले, यानी 12 अगस्त को, एयरपोर्ट लाइन से भी रोजाना सफर करने वालों की संख्या 50,000 पार कर गई।

- केंद्रीय सचिवालय–कश्मीरी गेट कॉरिडोर के अतंर्गत आईटीओ–मंडी हाउस विस्तार (0.92 कि.मी.) को 8 जून, 2015 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
- आईटीओ–बदरपुर सेक्शन (लाईन 6) के विस्तार बदरपुर–एस्कॉर्ट्स मुजेसर (फरीदाबाद) मेट्रो स्टेशन सेक्शन (13.875 कि.मी.) को 6 सितंबर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
- जहांगीरपुरी–समयपुर बादली मेट्रो कॉरिडोर (4.0373 कि.मी.) को यात्री सेवाओं के लिए 10 नवंबर को हरी झंडी दिखाकर शुरू किया गया।
- 21 दिसंबर को डीएमआरसी ने ''ऑफ साइट'' सोलर पीवी पावर प्लांट की स्थापना करने के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसमें डीएमआरसी स्वच्छ सौर ऊर्जा से अपनी आंशिक ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विद्युत क्रय करार (पीपीए) करेगा।
- 31 देशों के लिए वीजा सेवाएं प्रदान हेतु 2 दिसंबर को शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन पर एक वीजा सुविधा केंद्र खोला गया।

PWD

लोक निर्माण विभाग

एलिवेटेड कॉरिडोर:

विकासपुरी से वजीराबाद तक बाहरी रिंग रोड सिग्नल फ्री

निम्नलिखित एलिवेटेड कॉरिडोर और फ्लाईओवर का कार्य पूरा होने के बाद बाहरी रिंग रोड का यातायात सिग्नल फ्री हुआः–

- विकासपुरी से मीराबाग तक एलिवेटेड कॉरिडोर
- मंगोलपुरी से मधुबन चौक तक एलिवेटेड कॉरिडोर
- मधुबन चौक से मुकरबा चौक तक एलिवेटेड कॉरिडोर
- भलस्वा, मुकुंदपुर और बुराड़ी चौक तक एलिवेटेड फ्लाईओवर

बारापुला नाले के ऊपर एलिवेटेड सड़क के फेज 2 का निर्माण

बारापुला एलिवेटेड कोरिडोर के फेज 2 के अंतर्गत सुगम यातायात के लिए चार रैंप पूरे किए जा चुके हैं। रैंप 'ए' और 'एच' को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से सीधे आश्रम, डीएनडी फ्लाईओवर और नोएडा की ओर जाने वाले ट्रैफिक को सुविधा देने के लिए खोल दिया गया है। रैंप 'बी' और 'सी' का निर्माण भी पूरा हो चुका है। आश्रम और डीएनडी से आने वाले और आईएनए और जेएलएन स्टेडियम की ओर जाने वाले वाहन सीधे बारापुला एलिवेटेड रोड पर जा सकता है। इस कार्य के पूरा हो जाने से सराय काले खान बस स्टैंड के सामने रिंग रोड पर अब जाम नहीं लगता और सफर का समय भी 15–20 मिनट कम लगता हैं।

संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर से वजीराबाद चौक तक नाले की दूसरी ओर जोन पी-1 में रिंग रोड के समानांतर सड़क

इस रोड का निर्माण बाहरी रिंग रोड से भीड़ कम करने के लिए तथा भलस्वा, मुकुंदपुर, बुराड़ी, संगम विहार, जगतपुर, वजीराबाद व आसपास की अन्य कालोनियों के स्थानीय निवासियों को सुविधा देने के लिए किया गया।

स्वास्थ्य सेवा से संबंधी इन्फ्रास्ट्रक्चर

- दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा में बुनियादी सुधार के लिए लोक निर्माण विभाग 100 से ज्यादा आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक बना चुका है। राजधानी में कुल 1000 मोहल्ला क्लीनिक बनाए जाएंगे है।

- रोहिणी में बाबा साहब अंबेडकर मेडिकल कॉलेज भवन का निर्माण पूरा हो गया है।

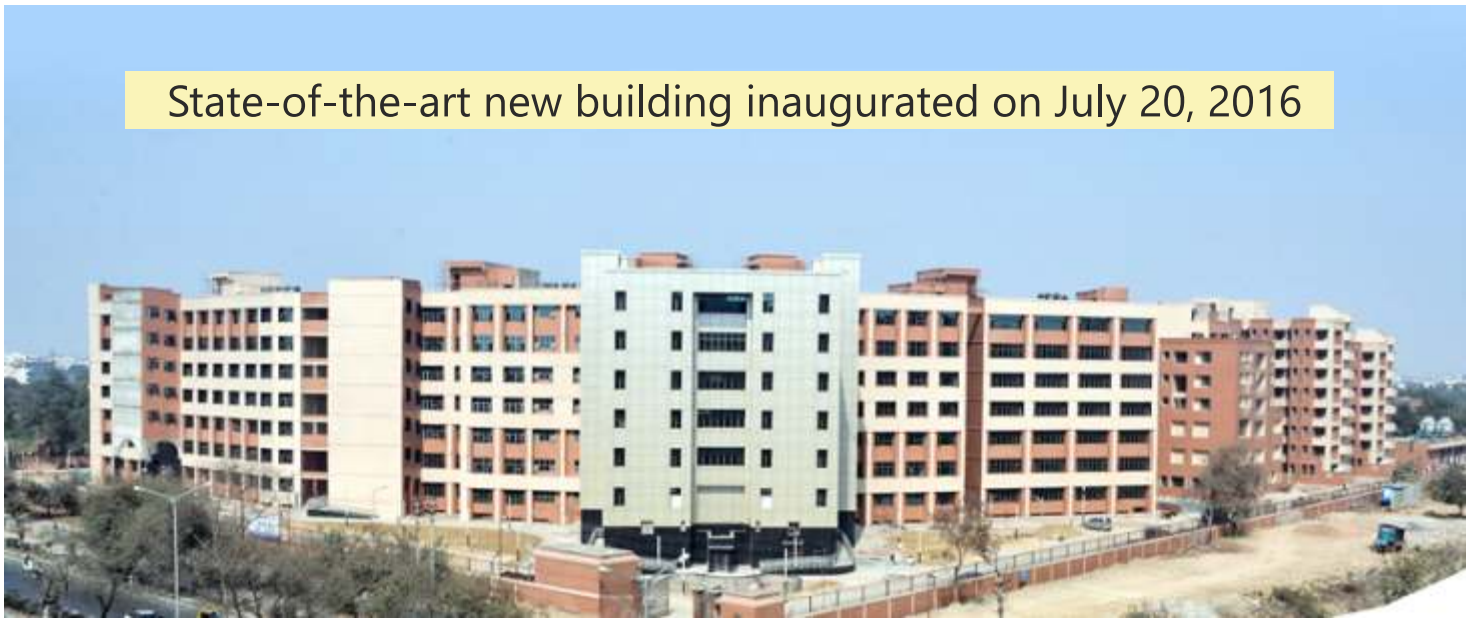

स्वास्थ्य शिक्षा के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूती

- पुष्प विहार में डिप्सार के लिए अकादमिक ब्लॉक

दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च के लिए 48.36 करोड़ रुपये की लागत से अकादमिक ब्लॉक का निर्माण किया गया है।

- द्वारका में डीडीयू कॉलेज का नया कैंपस

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने 208 छात्रों के लिए हॉस्टल और स्टाफ के लिए 9 क्वार्टरों सहित नए कैंपस का निर्माणकार्य का उद्घाटन किया। इस परियोजना की अनुमोदित लागत 169.43 करोड़ रुपये है और इस कॉलेज में 2,500 छात्रों की क्षमता है।

अन्य परियोजनाएं

मंडोली, जेल परिसर

मंडोली में जेल परिसर/आवासों का निर्माण कार्य 340 करोड़ रुपए की लागत के साथ पूरा किया गया। मंडोली जेल अतिरिक्त सुरक्षा के लिए 35.55 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कार्य प्रगति पर है। जेल संख्या 13 और 14 भी बनकर तैयार हैं। बाकी की जेलों में भी निर्माण कार्य मार्च 2017 तक कार्य पूरा हो जाएगा।

निर्माण कार्य प्रगति पर-

सड़क निर्माण

सराय काले खां को मयूर विहार फेज 1 से जोड़ने वाली तीसरे चरण की बारापुला एलिवेटेड रोड का निर्माण प्रगति पर है जो 2018 तक पूरा हो जाएगा। इस एलिवेटेड रोड के पूरा हो जाने के बाद मयूर विहार/यमुना पार के क्षेत्र से हवाई अड्डे/आईएनए/एम्स/दक्षिणी दिल्ली तक यातायात का आवागमन सुगम हो जाएगा।

शिक्षा

- मौजूदा स्कूलों में 1100 करोड़ रुपए की लागत से 20 पक्के स्कूल भवन और 6500 अतिरिक्त एसपीएस क्लासरूम के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। ये सभी कार्य जून 2017 तक पूरे हो जाएंगे।
- 50 करोड़ रुपए की लागत से रोहिणी में एनसीसी भवन और राजोकरी में नई पोलीटेक्नीक बिल्डिंग (मौजूदा एमपीसीसी) का कार्य प्रगति पर है और इनके जल्द ही पूरा होने की संभावना है।
- 280 करोड़ रुपए की लागत से सूरजमल विहार, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के पूर्वी दिल्ली के कैंपस का काम डीडीए से एनओसी मिलते ही शुरू हो जाएगा।
- रोहिणी में शहीद सुखदेव कॉलेज के नए कैंपस में अवसंरचनात्मक कार्यों के जून, 2017 तक पूरा होने की संभावना है। इसके लिए कुल अनुमोदित लागत 148.54 करोड़ रुपए है और कॉलेज में 2000 छात्रों की क्षमता है। कॉलेज का नया कैंपस नए अकादमिक वर्ष में चालू होगा।

अन्य परियोजनाएं

305 करोड़ रुपये की लागत से राउज एवेन्यू, डीडीयू मार्ग, नई दिल्ली में नई दिल्ली जिला अदालत का कार्य दिसंबर, 2017 तक पूरा हो जाएगा।

स्वास्थ्य सेवा की प्रगति परक परियोजना

- सेक्टर–9, द्वारका में 566 करोड़ रुपए की लागत से 700 बिस्तरों वाले सुपर स्पेशल्टी इंदिरा गांधी अस्पताल का निर्माण कार्य प्रगति पर है और दिसंबर 2018 में इसके पूरा होने की संभावना है।

- 183 करोड़ रुपए की लागत से कौशिक एंक्लेव, बुराड़ी में 200 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण प्रगति पर है और दिसंबर 2017 में इसके पूरा होने की संभावना है।

प्रशासनिक सुधार

APPLY ONLINE
TRACK ONLINE
District Delhi
SERVICE AT FINGER TIPS
COLLECT ONLINE

शपथपत्रों की समाप्ति से स्व-प्रमाणन की ओर

- विभिन्न विभागों, स्थानीय निकायों और दूसरे सरकारी संगठनों की ओर से मांगे जाने वाले 200 श्रेणियों के हलफनामों की समाप्ति। अब इसके स्थान पर आत्म–प्रमाणीकरण को अपना लिया गया है। मार्च 2015 में सरकार के गठन के एक महीने के भीतर ही कैबिनेट ने इस बारे में फैसला लिया था। इस निर्णय को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया।
- तत्काल विवाह पंजीकरण शुल्क को 10,000 रुपये से घटाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है। यह तत्काल आधार पर अपने विवाह को पंजीकृत करवाने वाले जोड़ों के लिए एक बड़ी राहत है। 20 जनवरी 2017 को इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी की गई।
- 19,830 छात्रों को विभिन्न प्रकार की आपदाओं का कुशलतापूर्वक सामना करने के लिए प्रशिक्षण देने के साथ उन्हें स्कूल सुरक्षा योजना के लिए भी तैयार किया गया। करीब 1400 शिक्षकों को स्कूल सुरक्षा और आपदा की स्थिति में व्यक्तियों की निकासी की योजना से परिचित करवाया गया।

भू–अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण

- एक आधुनिक, व्यापक और पारदर्शी भूमि रिकार्ड प्रबंधन प्रणाली को विकसित करने के लिए भू–अभिलेख कम्प्यूटरीकरण परियोजना का कार्यान्वयन किया गया। राजस्व विभाग के इंद्रप्रस्थ भू–लेख (दिल्ली भूमि रिकार्ड सूचना) ने नागरिकों की सुविधा के लिए डिजिटल हस्ताक्षर वाले आरओआर (रिकार्ड का अधिकार) जारी करने की सुविधा उपलब्ध करवाई।
- 186 गांवों के 33458 खातों की जमीन के भूमि रिकार्ड डिजिटल रूप में उपलब्ध। दिल्ली सरकार के सभी जिला कार्यालयों में 1 नवंबर 2016 के बाद डिजिटल रिकार्ड वाले खातों के लिए केवल डिजिटल हस्ताक्षर वाले आरओआर ही जारी किए जा रहे हैं।
- संबंधित जिला कार्यालयों के नागरिक सेवा केन्द्रों से आरओआर प्राप्त किए जा सकते हैं या उन्हें वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। यह सेवा चौबीस घंटे उपलब्ध है।

स्टाम्प और पंजीकरण

- जनवरी 2016 से शेयरों पर स्टांप शुल्क का संग्रह ऑनलाइन माध्यम से शुरू कर दिया गया है।
- मार्च 2016 से उप–रजिस्ट्रार कार्यालयों में होने वाले संपत्ति के पंजीकरण का कार्य ऑनलाइन कर दिया गया है। इसके साथ ही नागरिकों को संपत्ति के विवरण की जानकारी लेने के लिए ई–सर्च की सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। इससे कार्य में पारदर्शिता को बढ़ावा मिला है और नागरिकों के लिए इस सुविधा का लाभ उठाना सहज हो गया है।

ई–जिला परियोजना के लिए नागरिक कॉल सेंटर

- राजस्व विभाग के मुख्यालय में ई–जिला परियोजना के तहत नागरिकों के प्रश्नों, शिकायतों, सुझावों की प्रभावी निगरानी के लिए एक कॉल सेंटर की स्थापना
- यह कॉल सेंटर सुबह 09.30 बजे से शाम 6.00 बजे तक रविवार को छोड़कर सभी कार्य दिवसों में कार्य करता है। इस कॉल सेंटर में ई–डिस्ट्रिक्ट में उपलब्ध 33 सेवाओं के संबंध में सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। कोई भी प्रश्न या शिकायतों या सुझाव ई–मेलedistrictgrievance@gmail.com पर दिया जा सकता है।

जनोन्मुखी वित्त एवं कर सुधार

योजना प्रक्रिया में सार्वजनिक भागीदारी

- सरकार ने बुनियादी सिद्धांत के रूप में सार्वजनिक भागीदारी के साथ दिल्ली में विकास प्रक्रिया की शुरुआत की। सरकार ने नागरिकों को निर्णय लेने में और गवर्नेंस की प्रक्रिया में भागीदारी करने के लिए सशक्त बनाया।

- सरकार दिल्ली की जनता से बहुमूल्य सुझाव मांगकर दिल्ली की योजना प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित कर रही है। मुख्यमंत्री ने 2015–16 का बजट तैयार करने के लिए लोगों से सुझाव मांगते हुए अप्रैल 2015 में अपील की थी। जनता से करीब 1500 सुझाव प्रप्त हुए थे। आरडब्ल्यूए, एनजीओ, कॉरपोरेट सेक्टर के साथ प्रमुख समस्याओं और चुनौतियों पर भी चर्चा की गई थी और उनके द्वारा दिये गये सुझावों को बजट की तैयारी में इस्तेमाल किया गया था।

आर्थिक विकास

- वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2014–15 में 4,94,460 करोड़ रुपये था जो 2015–16 में 13 प्रतिशत की वृद्धि के साथ बढ़कर 5,58,745 करोड़ रुपये हो गया। वास्तविक रूप में स्थिर कीमतों पर, वर्ष 2015–16 में दिल्ली की अर्थव्यवस्था 8.34% की दर से विकसित हुई जबकी राष्ट्रीय जीडीपी में 7.6% की वृद्धि हुई थी। वर्ष 2011–12 में वर्तमान कीमतों पर अखिल भारतीय जीडीपी में दिल्ली के जीएसडीपी का हिस्सा 3.93% था जो 2015–16 में बढकर 4.12% हो गया, जबकि देश की कुल आबादी में दिल्ली का हिस्सा महज 1.43% ही है।

- सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के अग्रिम अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2015–16 वर्तमान कीमतों पर दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय 2,80,142 रुपये है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर 93,293 रुपये की प्रति व्यक्ति आय से लगभग तीन गुना अधिक है। जीएसडीपी में 82.3% हिस्सेदारी के साथ दिल्ली की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र प्रमुख है। इसके बाद उद्योग (15.5%) और कृषि क्षेत्रों (2.2%) का स्थान आता है।

वैट

- उपभोक्ताओं में खरीदारी करने के बाद उचित बिल लेने की आदत विकसित करने के लिए, सरकार द्वारा ''बिल बनवाओ, ईनाम पाओ'' स्कीम शुरुआत की गई है जिसके अंतर्गत सरकार उन उपभोक्ताओं को ईनाम देती है जो उचित बिल के साथ खरीदारी करते हैं। इस स्कीम को शानदार सफलता मिली है।

- पंजीकरण प्रक्रिया को फास्ट ट्रैक पर लाने के क्रम में, एक नई मोबाइल–डीवैट एम–सेवा की शुरुआत की गई है, जिसका इस्तेमाल कर डीलर मोबाइल ऐप के जरिए निरीक्षकों द्वारा पोस्ट–वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को अलग करते हुए खुद को चंद घंटों के भीतर रजिस्टर कर सकते हैं।

- व्यापार एवं कर विभाग ने एक कॉल सेंटर की स्थापना की है जहां प्रशिक्षित और योग्य कर्मचारी टोल फ्री नंबर पर कॉलर के सवालों का फटाफट समाधान करते हैं।

- अधिकारियों/कर्मचारियों को देय कर की वसूली के उनके कार्य में प्रोत्साहन देने के लिए, व्यापार एवं कर विभाग द्वारा सरकारी कर्मचारी ईनाम स्कीम का शुभारंभ किया गया और पहली बार सभी पात्र अधिकारियों/कर्मचारियों को ईनाम वितरित किए गए।

- व्यापार एवं कर विभाग ने डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से आवधिक रिटर्न फाइल करने के लिए अधिसूचना जारी की है,जिन व्यापारियों का टर्न ओवर एक करोड़ रुपए से अधिक बढ़ जाता उन्हें आवश्यक रिर्टन वैरिफिकेशन फॉर्म भरना जरूरी है

UD

शहरी विकास विभाग

हाल ही में दिल्ली सरकार ने शहरी विकास मंत्रालय और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित 'यूनिफाईड बिल्डिंग बाई–लॉ' के आधार पर दिल्ली की तीनों नगर निगमों में इसके कार्यान्वयन के लिए अधिसूचना जारी की है।

अनधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्य

दिल्ली के शहरी विकास विभाग ऐसी सभी अनाधिकृत कॉलोनियों (जिनके लगभग 50 प्रतिशत क्षेत्र पर निर्माण हो चुका है, चाहे उन कालोनियों में दिल्ली विकास प्राधिकरण की अनुमति हो या न हो , में नियमानुसार विकास कार्य शुरू करेगा। ऐसी अनधिकृत कॉलोनियों, जिनमें वन विभाग और एएसआई की तरफ से कोई आपत्ति है, उनमें विकास कार्य शुरू नहीं किया जाएगा। इन कॉलोनियों में जीएसडीएल द्वारा तैयार किए गये ले–आउट प्लान के आधार पर विकास कार्य किया जाएगा। जीएसडीएल 702 कॉलोनियों का नक्शा भेज चुका है। इनमें से 509 कॉलोनियों के नक्शे, विकास कार्य शुरू करने के लिए कार्य निष्पादन एजेंसियों को भेजे जा चुके हैं। 152 कॉलोनियों पर वन विभाग और एएसआई विभाग की आपत्ति है। शहरी विकास विभाग जीएसडीएल द्वारा 41 अन्य कॉलोनियों के नक्शे, कार्य निष्पादन एजेंसियों को विकास कार्य शुरू करने के लिए भेजने की प्रक्रिया में है। वर्ष 2015–2016 के दौरान कार्य निष्पादन एजेंसियों (डीएसआईआईडीसी, पीडब्ल्यूडी, आई एंड एफसी, दिल्ली जल बोर्ड, उत्तर और दक्षिणी नगर निगम) द्वारा अनाधिकृत कॉलोनिया में विकास कार्यों पर 803.97 करोड़ रुपए खर्च किए गये।

Labour

श्रम विभाग

श्रमिक विकास मिशन का गठन

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मई 2015 के अवसर पर श्रमिक विकास मिशन का शुभारम्भ किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य न्यूनतम मजदूरी को सही रूप से लागू करना और निर्माण व अन्य श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं के रूप में मिलने वाली आर्थिक सहायता में वृद्धि करना है।

श्रमिकों के लिए हेल्प लाइन

निर्माण श्रमिकों के लिए एक हेल्प लाइन न. 155214 शुरू किया गया है। इस श्रमिक हेल्प लाइन पर पिछले दो सालों में 25563 शिकायतें/जानकारी संबंधित काल मिली और सभी शिकायतें/जानकारी से संबंधित कॉल का संतोषजनक ढंग से निपटारा किया गया।

मुआवजा मामलों के निपटान के लिए अतिरिक्त/विशेष अदालतें

श्रम विभाग ने 5 अतिरिक्त न्यायालय वरिष्ठ अधिकारी की अगुवाई में स्थापित करके कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के तहत क्षतिपूर्ति के 95 प्रतिशत मामलों (1135 केस) का निपटारा कर दिया, जिसकी माननीय उच्चन्यायालय ने प्रशंसा की है।

विभिन्न श्रम कानूनों के तहत मजदूरों को धनराशि की सहायता

पिछले 2 सालों में श्रम विभाग द्वारा विभिन्न श्रम कानूनों के तहत 58.08 करोड़ रूपए की धनराशि की सहायता 13,831 मजदूरों को दिया गया है।

बाल मजदूर मुक्ति अभियान

पिछले दो सालों में जिला श्रम विभाग की टास्क फोर्स द्वारा 150 बार औचक निरिक्षण कर 1114 बाल मजदूरों को मुक्त कराया साथ–ही–साथ 123 कारखानों/संस्थाओं को सील कर दिया गया जहॉ इन बच्चों से कार्य कराया जा रहा था और इनसे 15 लाख 40 हजार रूपए जुर्माने के तौर पर वसूल किया गया।

श्रमजीवी पत्रकारों और अन्य समाचार पत्र कर्मचारियों के विविध प्रावधान संशोधन विधेयक

शीतकालीन सत्र 2015 के दौरान विधानसभा में ऊपर उल्लेखित बिल पेश किया गया और विधेयक विधान सभा द्वारा पारित किया गया है। विधेयक में श्रमजीवी पत्रकारों और अन्य समाचार पत्र कर्मचारियों को उनके वैध मजदूरी सहित पर्याप्त मुआवजा सुनिश्चित करने का प्रावधान है।

श्रम विभाग के नए पहल

प्रक्रिया सरलीकरण (Process Simplification) :– विभाग द्वारा भवन निर्माण योजना की स्वीकृति और फैक्ट्री लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया और इसके लिए प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की संख्या में कमी की गई। फैक्ट्री मालिकों की सुविधा के लिए फैक्ट्री लाइसेंस की वैधता एक साल से बढ़ाकर 10 साल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। संविदा श्रम अधिनियम 1970 के अनतर्गत ठेकेदारों को दिए जाने वाले लाइसेंस के प्रार्थनापत्र के साथ लगाए जाने वाले 11 दस्तावेज कम कर दिए गए हैं और इनके स्थान पर केवल एक शपथ पत्र (Affidavit) लगाना होगा। यह लाइसेंस शीघ्र ही e-District Portal पर उपलब्ध होगा। इससे इंस्पेटकर राज को समाप्त करने में सहायता मिलेगी साथ ही साथ फैक्ट्री मालिकों को सुविधा उपलब्ध होगी।

ऑन लाईन सेवाएं (Online Services):– विभाग द्वारा 11 सेवाओं को प्राथमिकता के आधार पर ऑनलाईन किया जा रहा है जिसमें से दो सेवाओं शॉप एंड इस्टेबलिशमेंट एक्ट (Shop & Establishment Act) के अन्तर्गत लाइसेंस और फैक्ट्री भवन निर्माण योजना लाइसेंस को ऑनलाईन कर दिया गया है।

ऑन लाईन सेवाएं प्रारम्भ करने के बाद भवन निर्माण योजना की स्वीकृति में मात्र तीन दिन का समय लगता है जबकि पहले यह स्वीकृति 3–4 महीने में दी जाती थी। इसी प्रकार फैक्ट्री लाइसेंस जारी करने का समय भी 3 महीने के स्थान पर सिर्फ एक सप्ताह हो जाएगा। e-Payment Gateway लागू करने प्रक्रिया भी चल रही है जिसके बाद यह सेवा भारत सरकार की eBiz Portal पर उपलब्ध होगी।

दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड

- बोर्ड की 18 योजनाओं द्वारा निर्माण श्रमिकों को सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से 7 योजनाओं का लाभ पंजीकरण की तिथि से ही मिलना प्रारम्भ हो गया है। ये योजनाएं हैं 1) प्रसुति सहायता 2) विकलांगता सहायता 3) एक्स गेसिया 4) अंतिम दाह संस्कर सहायता 5) आकस्मिक मृत्यु सहायता 6) कक्षा 1 से 12 तक शिक्षा के लिए सहायता 7) गर्भपात होने की स्थिति में दी जाने वाली सहायता
- बोर्ड में कुल 4 लाख 11 हजार 5 सौ 76 (411576) निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण किया जा चुका है। इसमें 1,68,044 लाइव सदस्य हैं।
- बोर्ड द्वारा अब तक कुल 2200 करोड़ रूपए सेस एवं ब्याज के रूप में संग्रहित किए गए।

दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की नई पहलबोर्ड की कल्याणकारी योजनाओं की सोशल ऑडिट

बोर्ड द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं एवं अन्य योजनाओं पर किए गए खर्च का सोशल ऑडिट कराने का निर्णय लिया गया है। इन योजनाओं का भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों पर पड़ने वाले प्रभावो का भी अध्ययन किया जाएगा। जिससे अगर उसमें और सुधार करने की जरूरत पड़े तो सरकार उस संदर्भ में जरूरी कदम उठा सके

भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों का बीमा

निर्माण मजदूरों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना जल्द लायी जाएगी। इसके लिए बीमा कंपनियों से बातचीत की जा रही है। इस व्यवस्था को लागू करवाने के लिए 5 सदस्यीय एक कमेटी बनाई गई है ।

बोर्ड (मुख्यालय) एवं जिला में e-District

श्रमिकों के पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए बोर्ड के आफिस एवं जिला कार्यालयों में e-District लागू करने की योजना तैयार हो गई है। इसके लिए बोर्ड के सभी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। यह भी फैसला लिया गया कि सभी तरह की कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित पैसा श्रमिकों के खाते में सीधे जाए। आगे मजदूरों के पंजीकरण के लिए बैंक अकाउंट जरूरी किया जाएगा ।

निर्माण मजदूरों को स्किल ट्रेनिंग

मजदूरों को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वे अपने अपने कार्यों में दक्ष हो सके। निर्माण मजदूरों को सरकारी एजेंसियों NBCC, DMRC द्वारा स्कील ट्रेनिंग दी जाएगी।

छात्रवृत्ति

अब तक बोर्ड द्वारा केवल दिल्ली सरकार के स्कूलों में ही पढ़ रहे निर्माण श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति/आर्थिक सहायता दी जाती है परंतु अब सरकार ने यह निर्णय लिया है कि दिल्ली नगर निगम एवं एन डी एम सी के स्कूलों में पढ़ रहे निर्माण मजदूरों के बच्चों को भी छात्रवृत्ति/सहायता दी जाएगी। छात्रवृत्ति सीधे निर्माण मजदूर के खाते में जाए इस व्यवस्था के सरलीकरण के लिए एक कमेटी अपनी सुझाव देगी।

गाँवों का विकास

2 करोड़ रुपये प्रति गांव के विकास के लिए निर्धारित

दिल्ली के गांव के विकास के लिए निम्नलिखित कार्यों को ग्रामीण विकास बोर्ड द्वारा किया जा रहा है।

- सड़कों का निर्माण / लिंक सड़कों / गांव के सड़कों की मरम्मत
- जल निकासी की सुविधा की व्यवस्था , मुख्य रूप से बाढ़ से बचाने के लिए
- श्मशान भूमि, पार्क, खेल के मैदानों, व्यायामशाला आदि का विकास
- तालाबों / जल निकायों का विकास
- पीने के पानी की सुविधा, स्ट्रीट लाइट आदि जैसे अन्य जरूरत

वर्ष 2015–16 और 2016–17 के दौरान ग्रामीण विकास बोर्ड द्वारा किए गए अनुमोदित कार्यों का विवरण: –

कार्यों का प्रकार	कार्यों की मंजूरी	
	2015-16	2016-17
सड़क	135	44
ड्रेन्स	19	10
पॉन्डस/वॉटर बॉडी	15	05
कम्यूनिटी सेंटर	01	-
पार्क	03	02
दाह संस्कार केंद्र	20	04
व्यायामशाला/खेल का मैदान	03	01
कुल	**196 (रुपये–235.10 करोड़)**	**66 (रुपये–59.96 करोड़)**

दिल्ली की बुनियादी कृषि सांख्यिकीय डेटा :–

- दिल्ली के कुल भौगोलिक क्षेत्र : 1483 वर्ग किमी
- वर्तमान में कृषि–बागवानी गतिविधियाँ : 30,000 हेक्टेयर, कृषि जनगणना 2010–11 के आधार पर
- किसानों की कुल संख्या (कृषि के अनुसार) : 20,000 , कृषि जनगणना (2010–11) के आधार पर

Irrigation and Flood

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग

- सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा छठ घाट के निर्माण के लिए विशेष अभियान
- छठ घाट के निर्माण के संदर्भ में एक कमेटी बनाई गई ताकि कार्य पर लगातार निगरानी रखी जा सके ।
- छठ घाट के निर्माण के लिए बजट में अलग से प्रावधान

Animal Husbandry

पशुपालन विभाग

- अक्टूबर 2016 में पक्षियों में पाए गए खतरनाक वाइरस H5N8 (वर्ड फ्लू) की रोकथाम के लिए युद्ध स्तर पर कार्रवाई
- तीन हफ्ते के अंदर इसपर नियंत्रण , वो भी बिना किसी प्रभावित पक्षी को मारे बिना।

खाद्य आपूर्ति विभाग

दिल्ली सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की लगभग 2500 अधिकृत राशन की दुकानों के माध्यम से लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरित कर रही है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने, खाद्यान्न की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने और वितरण श्रृंखला को मजबूत करने के लिए सभी लाभार्थियों को शत प्रतिशत आधार कार्ड से जोड़ा है। दिल्ली में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कुल 19.46 लाख राशन कार्ड चिन्हित है। दिल्ली में अब तक लगभग 72 लाख लोग इस श्रृंखला से जुड़ चुके हैं।

ई–राशन कार्ड

प्रचालित ई–राशन कार्ड की सुविधा दिल्ली की जनता को समर्पित कर दी गई है। दिल्ली के 6.91 लाख राशन कार्ड धारकों ने ऑनलाइन सुविधा के तहत राशन कार्ड डाउनलोड कर सुविधा का लाभ उठाया है। इस माध्यम से लाभार्थियों को पारदर्शी और खाद्यान्न की सही वितरण प्रणाली का लाभ मिला है। कोई भी लाभार्थी http://nfs.delhi.gov.in पर जा कर राशन कार्ड नंबर और दूसरी जरूरी जानकारियां विभाग के पोर्टल पर डालकर मोबाइल फोन पर पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। पासवर्ड दर्ज करक पोर्टल से ई–राशन कार्ड ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगा जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में संग्रहीत करके प्रिंट लिया जा सकता है और राशन प्राप्त किया जा सकता है।

बॉयोमीट्रिक प्रमाणीकरण

दिल्ली में 40 एफपीएस (राशन की दुकान) पर पायलट परियोजना के तहत बॉयोमीट्रिक प्रमाणीकरण के बाद राशन जारी किया जा रहा है। यह प्रयोग वास्तविक लाभार्थियों को राशन का वितरण सुनिश्चित करती है। सभी एफपीएस (पीओएस) को बॉयोमीट्रिक प्रमाणीकरण की व्यवस्था से जोड़ा जा रहा है, जिससे राशन की कालाबाजारी को रोका जा सकता है।

राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी

राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी को प्रायोगिक आधार पर दिल्ली छावनी विधान सभा क्षेत्र में लागू किया गया है। राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी के तहत एक निर्वाचन क्षेत्र में स्थित किसी भी राशन दुकान से लाभार्थी राशन प्राप्त कर सकता है। इस पोर्टेबिलिटी व्यवस्था से लाभार्थी बेहतर सेवा प्राप्त कर सकता है।

राशन आवाजाही की निगरानी

भारतीय खाद्य निगम से दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (DSCSC) को खाद्यान्न की आपूर्ति होती है। इसकी निगरानी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जा सकती है। कार्ड धारकों को उनका राशन सुचारू रूप से मिलना सुनिश्चित कराने के लिए ऑनलाइन प्रणाली से राशन कार्ड धारकों और राशन वितरकों को एक साथ ही राशन वितरण के बारे में जानकारी का एसएमएस मिल जाता है। इससे राशन के कालाबाजारी पर रोकथाम में मदद मिलती है।

नया खाद्य सुरक्षा पोर्टल

दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुगम बनाने के उद्देश्य से नागरिकों के लिए एक पोर्टल www.nfs.delhi.gov.in विकसित किया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए इस नए पोर्टल के माध्यम से लाभाथियों को जोड़ा जा रहा है। राशन कार्ड धारकों को संबंधित सेवाओं की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा रही है।

राशन हेल्पलाइन/कॉल सेंटर नंबर (1967):

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, राशन हेल्पलाइन नंबर 1967 पर आने वाली जनता की शिकायतों/सुझावों को कॉल सेंटर के कर्मचारियों के माध्यम से संबंधित अधिकारियों के पास भेजकर निराकरण करवा रहा है । कॉल सेंटर हेल्पलाइन नंबर (1967) पर मिलने वाली शिकायतों/सुझावों से राशन वितरण से सम्बंधित समस्याओं के निराकरण में अपूर्व सफलता मिली है।

राशन वितरण में समय की बाध्यता समाप्त

दिल्ली सरकार ने विभाग के निरीक्षकों द्वारा संचालित वितरण प्रारंभ प्रणाली को खत्म करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राशन वितरण का कार्य अब हर महीने के पहले दिन शुरू होता है और राशन कार्ड धारक महीने भर राशन दुकानों से राशन प्राप्त कर सकते हैं। नई प्रणाली से राशन कार्ड धारकों और एफपीएस लाइसेंसधारियों को बड़ी राहत मिली है।

महिला ,एवं बाल विकास

महिला सशक्तिकरण (महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ)

- महिला एवं बाल विभाग ने घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के कारगर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए 18 संरक्षण अधिकारियों को नियुक्त किया है, जो कि दिल्ली के प्रत्येक जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं।

- इन संरक्षण अधिकारियों को पीड़ित महिलाओं से शिकायतें प्राप्त होते हैं। ऐसे मामलों को मिलने के बाद ये अधिकारी अधिनियम के अंतर्गत उपबंधों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं । विभाग ने इसके लिए संरक्षण अधिकारियों की भर्ती के नियम अधिसूचित कर दिए हैं तथा और छह और प्रोटैक्शन अधिकारियों की नियुक्ति का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं निदान) अधिनियम, 2013 का कार्यान्वयन।

- अभी तक इस कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए निम्न कदम उठाए गए हैं:
  i. जिला मजिस्ट्रेटों को जिला अधिकारियों के रूप में नामित किया गया है, जो शीघ्र ही दस से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों से यौन उत्पीड़न की शिकायत प्राप्त करने के लिए स्थानीय शिकायत समिति का गठन करेंगे।
  ii. 234 विभागों/स्वायत्त निकायों/आयोगों/बोर्डों ने विभागीय शिकायत समिति को अधिनियम के तहत दिए गए उपबंधों के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति का गठन करने की सूचना दे दी गई है।
- विभाग की महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ शाखा ने तेजाब फेंकने की घटना की पीड़िताओं की दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से मुआवजा प्राप्त करने में सहायता की।
- द्वारका में कामकाजी महिलाओं के लिए कात्यायनी हॉस्टल बनकर तैयार है जो कि जल्द ही शुरू हो जाएगा।
- महानगर में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग ने संयुक्त राष्ट्र–महिला भागीदारी सें ''सुरक्षित दिल्ली कार्यक्रम'' परियोजना की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य महिलाओं और लड़कियों के लिए सुरक्षित और समावेशी नगर का वातावरण बनाना है, जिससे वे यौन हिंसा और उसके भय या संभावना से मुक्त होकर निर्भयता से जीवन व्यतीत करने में सक्षम हो सकें।

समाज कल्याण

वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन (वृद्धावस्था सहायता का विस्तार)

- इस स्कीम के तहत 1000 रुपये प्रति माह की दर से उन बेसहारा वृद्धजनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिनके पास जीवन निर्वाहन का कोई साधन नहीं है। 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली सहायता राशि को 1000 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति माह कर दिया गया है।
- वृद्धावस्था पेंशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सिस्टम के जरिए भेजी जाती है। पिछले दो वर्षों का विवरण निम्न है:–

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	बजट अनुमान(करोड़ रुपए में)	व्यय (करोड़ रुपए में)
2015-16	3,88,471	608.80	602.90
2016-17	3,82,665	610.00	409.36 (दिसंबर 2016 तक)

वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवासीय मनोरंजन केंद्र

- आवासीय मनोरंजन केंद्र वरिष्ठ नागरिकों को विश्राम की सुविधाएं देने के साथ अच्छे से समय बिताने के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित करते हैं। ये वरिष्ठ नागरिकों को उनके परिवारों के साथ जुड़ने में मदद देते हैं।
- इन केंद्रों को एक बार मिलने वाला 75,000 रुपए का अनावर्ती अनुदान और 20,000 रुपए प्रति माह का आवर्ती अनुदान प्रदान किया जाता है। जिससे वे परिचालन व्यय की व्यवस्था कर सकें। वर्तमान में, दिल्ली में 94 मनोरंजन केंद्र चल रहे हैं।
- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए मनोरंजन केंद्र चलाने की योजना के तहत सहायता अनुदान की पहली किश्त 57 मनोरंजन केंद्रों को जारी कर दी गई है।
- दिल्ली में वरिष्ठ नागरिकों के मनोरंजन केंद्र चलाने के लिए 228 नए आवेदन प्राप्त हुए। विभिन्न जिलों के अधिकारियों ने कुल 34 मामलों की अनुशंसा की। सहायता अनुदान समिति ने हरेक मामले की जांच की और इस योजना में सहायता अनुदान जारी करने के लिए आठ मामलों की अनुशंसा की।

पर्यटन

- दिल्ली की समृद्ध विरासत को बाहर से आए पर्यटकों के सामने प्रदर्शित करने के उद्देश्य से दिल्ली पर्यटन विभाग ने पुरानी दिल्ली के आसपास जामा मस्जिद और चाँदनी चौक इलाके में पैदल यात्रा की अनूठी शुरुआत की। 'सिटी वाक' और 'रिक्शा यात्रा' शहर की गौरवशाली विरासत और विशिष्ट वास्तुकला से पर्यटकों को रूबरू कराने में मील का पत्थर साबित हो रही है।

- दिल्ली को एक सांस्कृतिक स्थल के रूप में प्रदर्शित करने के लिए पर्यटन विभाग ने ने 'गार्डन टूरिज्म फेस्टिवल', 'आम महोत्सव', 'दिल्ली के पकवान', 'अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव', 'विंटर कार्निवाल' आयोजित करने जैसे विशिष्ट कदम उठाए हैं।

- पर्यटन क्षेत्र को मजबूती एवं प्रशिक्षित मानव शक्ति प्रदान करने के उददेश्य से पर्यटन विभाग ने स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों के लिए दिल्ली हाट, पीतमपुरा में 'पर्यटन और यात्रा प्रबंधन' में कम अवधि पाठ्यकमों की शुरूआत की है। इसका संचालन दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट द्वारा किया जा रहा है।

ढाँचागत परियोजनाएं : सिग्नेचर ब्रिज

- पर्यटन विभाग की ओर से उत्तर–पूर्वी दिल्ली में मौजूदा वजीराबाद यमुना पुल पर 1500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक 'सिग्नेचर ब्रिज' का निर्माण किया जा रहा है। भारत में बनने वाला अपनी तरह का यह पहला पुल है। इस पुल को थामने के लिए यमुना नदी के उपर 251 मीटर केबल का इस्तेमाल किया गया है। इस अत्याधुनिक ब्रिज की ऊँचाई कुतुब मीनार से भी दुगनी होगी। इसकी डिजाइन जर्मनी की कंपनी Schliach Bergermann ने तैयार किया है,जबकि निर्माण Gammon (India), C-Cidade (Brazil) और Tensacciai (Italy) के सम्मिलित प्रयासों से किया जा रहा है।

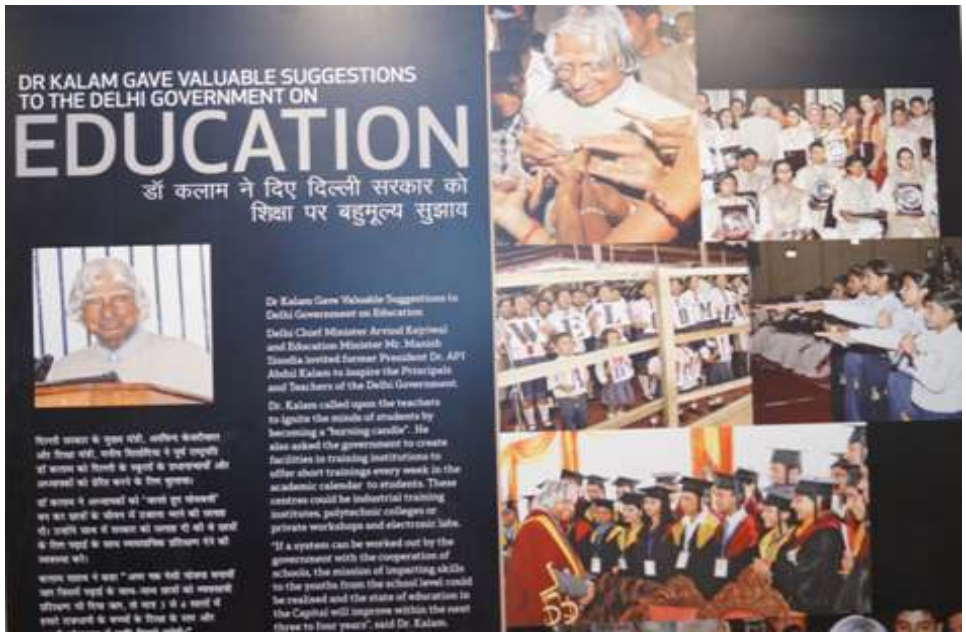

कलाम मेमोरियल

- भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ.एपीजे अब्दुल कलाम की विरासत को भारतीयों के दिलों में जिंदा रखने के लिए पर्यटन विभाग ने 'दिल्ली हाट' में एक संग्रहालय का निर्माण किया है। इस संग्रहालय में डॉ.कलाम के विचारों और संदेशों को सँजोया गया है।

राज्य शिक्षा पुरस्कार 2016

पर्यटन विभाग ने दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के सहयोग से त्यागराज स्टेडियम में 5 सितंबर 2016 को 'राज्य शिक्षक पुरस्कार समारोह' का आयोजन किया। दिल्ली सरकार द्वारा शिक्षकों को सम्मानित करने और लोगों के बीच शिक्षा को बढावा देने के लिए देश में पहली बार इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में निजी एवं सरकारी विद्यालयों के 100 शिक्षकों को सम्मानित किया गया।

ऐडवेंचर पार्क

- पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए दिल्ली पर्यटन विकास निगम ने 'पन्चेंद्रिय पार्क' में एक ऐडवेंचर पार्क का निर्माण किया है। यह पर्यावरण अनुकूल परियोजना है। यह पार्क हरे–भरे बगीचों से घिरा है जहाँ आत्मिक शाँति महसूस होती है।

फिल्म शूटिंग स्थल के रूप में दिल्ली को बढ़ावा

दिल्ली में फिल्म शूटिंग को बढावा देने के लिए पर्यटन विकास निगम 'एकल खिड़की स्वीकृति तंत्र' विकसित करने की प्रक्रिया में है। इसके लागू हो जाने पर फिल्म निर्माता कम्पनियों को दिल्ली में फिल्म शूटिंग की इजाजत के लिए विभिन्न विभागों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। एक ही विभाग सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने और जरूरी दिशा निर्देश देने में सक्षम होगा।

पर्यटन विभाग की वर्ष 2017-18 की परियोजनाएँ

पर्यटन विभाग की वर्ष 2017–18 की परियोजनाओं में कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन को कुतुब मीनार से जोड़ने के लिए एलिवेटिड वॉक–वे का निर्माण और ऐडवेंचर पार्क के विकास के अलावा 'दिल्ली हाट' में फूड कोर्ट का सौन्दर्यीकरण प्रस्तावित है।

कला, संस्कृति एवं भाषा

राजधानी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक आयोजन

- हिन्दी अकादमी ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के लालकिले पर कवि सम्मेलन, सेंट्रल पार्क में कबीर सूफी संगीत और श्रीराम सेंटर ऑफ आर्ट आडिटोरियम में नाटक उत्सव का आयोजन किया।

- पंजाबी अकादमी ने गुरु गोबिंद सिंह जी के 350 वे जन्मोत्सव पर एक बड़े उत्सव का आयोजन, श्शास्त्रीय संगीत उत्सव, गुरबानी गवेह भाई, पंजाबी बेसाखी मेला, परम्परिक पंजाब संगीत महोत्सव, दिल्ली सेलिब्रेट के अन्तर्गत सालाना थिएटर एवं महिला थिएटर उत्सव का आयोजन किया। ग्रीष्म अवाकश के दौरान बच्चों में आत्मविश्वास भरने के लिए चिल्ड्रन थिएटर और फॉक डांस के 8 वर्कशॉपों का विभिन्न क्षेत्रों में आयोजन किया गया।

- उर्दू अकादमी ने दिल्ली के लालकिले पर ड्रामा फेस्टिवल/चिल्ड्रन थिएटर वर्कशाप, सेमिनार और पारम्परिक उर्दू फेस्टिवल का आयोजन किया। इनके अतिरिक्त साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम जिनमें मुशायरा, कव्वाली, और गजल के कार्यक्रमों को शामिल किया गया। अकादमी की ओर से साहित्यिक विद्ववानों को बहादुर शाह जफ़र और पंडित ब्रिजमोहन दत्तात्रे केफी पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया।

- संस्कृत अकादमी ने नुक्कड़ नाटकों के अलावा सम्मर योगा कैम्प, संस्कृत स्पीच कैम्प, वैदिक स्पीच उत्सव और संस्कृत संगीत उत्सव का आयोजन किया।

- सिंधि अकादमी ने भारत की सीमा से सटे क्षेत्रो के साथ भारत ऐतिहासिक और सामाजिक–सांस्कृति सम्बन्धों को दर्शाने के लिए राश्ट्रीय सेमिनार–सिंध का आयोजन किया। चेटीचंद उत्सव, चिल्ड्रन वर्कशाप, सिंध समुदाय पर सिंध म्युजिक वर्कशाप और झूलेलाल छलिया महोत्सव का भी आयोजन किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सिंध कवि सम्मेलन का आयोजन किया। सिंधी ड्रामा फेस्टिवल, सुहानी सुरीली शाम, होली महोत्सव और शास्त्रीय संगीत–नवान तराना होली–ए–जा का आयोजन किया।

- मैथिली–भौजपुरी ने छठ पूजा, राष्ट्रीय कवि सम्मेलन, बिहार सम्मान समारोह और युवा उत्सव का आयोजन किया।
- साहित्य कला परिशद ने पूरे वर्श चलने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के अलावा चिल्ड्रन समिट 2016 के विजेताओं के लिए एक शाम और यमुना आरती का आयोजन किया। दिल्ली सेलिब्रेट के अन्तर्गत विभिन्न सांस्कृति कार्यक्रमों जैसे भक्ति संगीत, ठुमरी रामायण, दिल्ली शास्त्रीय संगीत उत्सव, पुराने किला पर डांस कार्यक्रम, युवा उत्सव, मोहन राकेश सम्मान, भरतमुन रंग उत्सव, एन्युवल आर्ट एग्जिबिशन, युवा नाट्य समारोह, महाविद्यालय नाट्य उत्सव, यूथ फेस्टिवल, वामा–वोमन आर्टिस्ट एग्जिबिशन, भारतेन्दू नाट्य उत्सव, मिर्जा गालिब की पुण्यतिथि, सरस्वती वंदना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, शाम–ए–दिल्ली घराना, नेहरू पार्क में रागीरी (जाकिर हुसैन द्वारा प्रस्तुत), गालिब की हवेली, कुदसिया घाट एवं तालकटोरा घाट इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया है।
- डॉ गोस्वामी गिरधारी लाल शास्त्री प्राचार्य विद्या प्रतिष्ठान ने विद्यालयों और गुरूकुलों की वर्तमान स्थिति और उनकी उन्नति के लिए एक संगोष्ठी का आयोजन किया। विद्यालयों में संस्कृत को पढाना शुरू किया गया और जिन विद्यालयों में संस्कृत परीक्षा बंद कर दी गई थी उनमे उसे फिर से शुरू करवाया गया।
- पुरालेख
- पुरातत्व विभाग 2.00 लाख से ज्यादा दस्तावेजों का संरक्षण कर रहा है। विभाग ने दिल्ली सरकार के सभी विभागों को ऐसे दस्तावेज जिनकी भविष्य में आवश्यकता हो सकती है, को पुरातत्व विभाग को भेजना का अनुरोध किया है जिससे उन्हें लम्बे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। पुराने दस्तावेजों की पूर्ण सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए सभी पुरातत्व विभाग के सभी कार्यालयों जहां पर पुराने दस्तावेज रखे गये है वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगवाए गये है। आईटीओ पर एक एग्जिबिशन का आयोजन किया गया जिसमें दिल्ली के इतिहास को दर्शाया गया। विभाग एनआईसीएसआई के सहयोग से ई–आफिस के कार्यान्वयन के तहत 7.5 लाख पेपरो का कम्प्यूटरीकरण किया है।

पुरातत्व

- पुरातत्व विभाग ने 143 स्मारकों के दस्तावेजों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है। क्षेत्रीय महत्व के 16 स्मारकों के नवीनीकरण और नेशनल जूलॉजी पार्क में अजीमगंज की सराय के संरक्षण का कार्य प्रगति पर है। डीटीटीडीसी के सहयोग से आइएनए दिल्ली हाट में कलाम संग्रहालय की स्थापना की गई जिसका उद्घाटन 30.7.2016 को दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने किया।

- विभाग ने कार्यालयी भाषा हिन्दी और दूसरी कार्यालयी भाषा उर्दू और पंजाबी के विकास के लिए टंकण और आशुलिपिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया।

- विभिन्न विधानसभाओं क्षेत्रों में एनजीओ द्वारा चलाए जा रहे पुस्तकालयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है।
- विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष मिर्जा गालिब की जन्मशताब्दी का भी आयोजन किया जा रहा है।

TOMB at Mehrauli Archaeological Park

JHARNA, Mehrauli

IMAMBARA at Qutb Road

TOMB (on raised plateform)

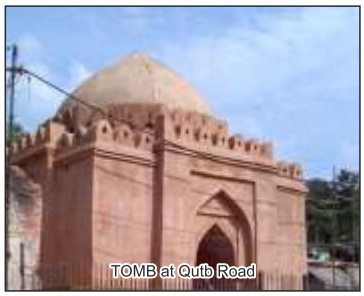
TOMB at Qutb Road

JHARNA, Mehrauli

BAOLI at DWARKA SECTOR-12

TOMB, Katwaria Sarai

TOMB at Greater Kailash-I

CHAUMCHI KHAN'S TOMB at Mehrauli

TOMB, Gautam Nagar

NORTHERN GUARD HOUSES, Northern Ridge

SOUTHERN GUARD HOUSES, Northern Ridge

TOMB at Sadhna Enclave

BARADARI at Sadhna Enclave

MOSQUE AT VASANT VIHAR

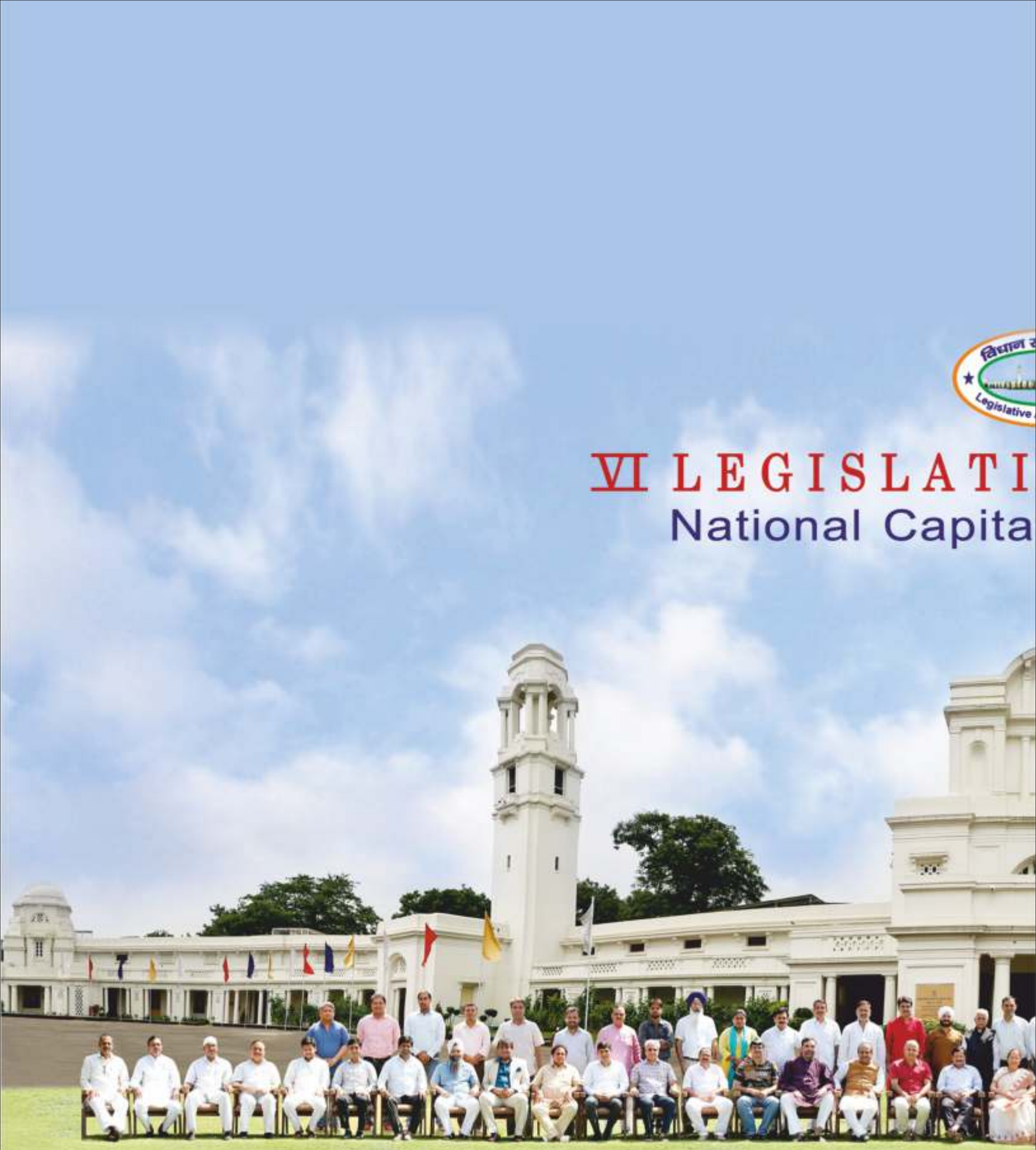

Sitting (Left to Right)

Sh. Sahi Ram, Sh. Jagdish Pradhan, Sh. Shiv Charan Goel, Sh. Rajesh Rishi, Sh. Prakash Jarwal, Sh. Naresh Yadav, Sh. Dinesh Mohaniya, Sh. Jarnail Singh, Col. Devinder Kumar Sehrawat, Sh. Shreedutt Sharma, Sh. Saurabh Bhardwaj, Sh. Kailash Gahlot, Sh. Sukhbir Singh Dalal, Commando Surender Singh , Sh. Gopal Rai (Hon'ble Minister), Sh. Vijender Gupta (Hon'ble Leader of Opposition), Sh. Manish Sisodiya (Hon'ble Deputy Chief Minister), Sh. Arvind Kejriwal (Hon'ble Chief Minister), Smt. Sumitra Mahajan (Hon'ble Speaker Lok Sabha)

Standing (Left to Right)

Sh. Adarsh Shastri, Sh. Nitin Tyagi, Sh. Manoj Kumar, Sh. Som Dutt, Sh. Gulab Singh, Sh. Akhilesh Pati Tripathi, Sh. Om Prakash Sharma, Sh. Praveen Kumar , Sh. Avtar Singh , Ms. Sarita Singh, Sh. Rajesh Gupta, Sh. Kartar Singh Tanwar, Sh. Mahendra Yadav, Sh. Naresh Balyan, Sh. Jarnail Singh, Sh. S.K. Bagga, Sh. Ajay Dutt,

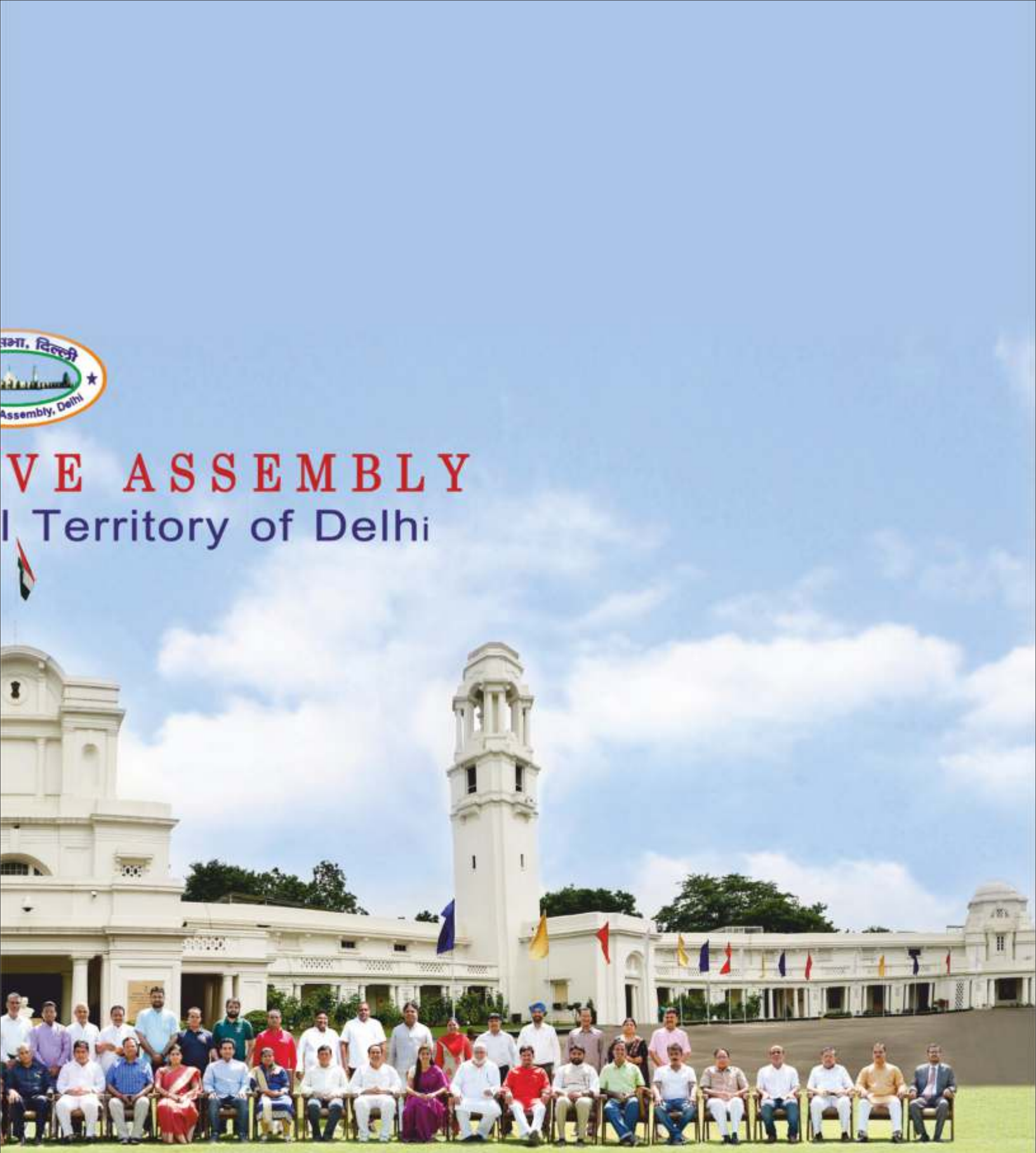

Sh. Ram Niwas Goel (Hon'ble Speaker), Sh. Sandeep Kumar, Sh. Satyendra Jain (Hon'ble Minister),
Smt. Bandana Kumari (Hon'ble Deputy Speaker), Shri Kapil Mishra (Hon'ble Minister), Ms. Rakhi Birla, Sh. Girish Soni, Sh. Asim Ahmed Khan,
Ms. Alka Lamba, Sh. Mohd. Ishraq Khan, Sh. Sanjeev Jha, Sh. Vishesh Ravi, Sh. Pankaj Pushkar, Sh. Ajesh Yadav, Sh. Anil Kumar Bajpayi,
Sh. Raghuvinder Shokeen, Sh. Hazari Lal Chauhan, Sh. Jitender Singh Tomar, Sh. Prasanna Kumar Suryadevra (Secretary, Delhi Legislative Assembly)

Sh. Madan Lal, Sh. Vijender Garg, Sh. Somnath Bharti, Sh. Mohinder Goyal, Sh. Rituraj Govind, Sh. Ved Prakash, Sh. Amanatullah Khan,
Sh. Narayan Dutt Sharma, Sh. Imran Hussain (Hon'ble Minister), Sh. Raju Dhingan, Sh. Sharad Kumar, Smt. Pramila Tokas,
Sh. Rajendra Pal Gautam, Sh. Jagdeep Singh (Chief Whip), Ch. Fateh Singh, Ms. Bhavna Gaur, Sh. Pawan Kumar Sharma.

25 August 2015

MEGA
दिल्ली
DOORDARSHAN

DL 1CT 305